

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन याचिका ओ0ए0सं0-90/2020 प्रमोद बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.08.2020 के सम्बन्ध में आख्या:-

उपरोक्त संदर्भित याचिका के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा नई दिल्ली द्वारा दिनांक 17.08.2020 को निम्न आदेश पारित किया गया है:-

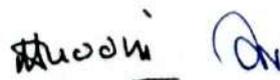
- 1- Grievance in this application is inter - alia is against District Survey report for riverbed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020. The mining sites are within 1 K.M. from Kalesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF&CC order dated 08.08.2019. Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage in Saharanpur. Cluster Impact Assessment has not been done as required. The sand mining has been continuing even during the locked down period. The above report shows that there is noncompliance of the direction as the task has been assigned to the Technical Committee at the District level which does not comprise of experts. The micro assessment of the area is required to be done with the involvement of experts.
- 2- A report was sought from District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. vide order dated 29.06.2020.
- 3- Accordingly, a report has been filed on 13.07.2020 to the effect that leases were granted prior to the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2020. However, the fact remains that the replenishment study is required even de hors the said Guidelines, the objections of the applicant may be responded to by the Department. The applicant is at liberty to file a fresh representation before the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. within one week from today with reference to the report filed on 13.07.2020.
- 4- Let a fresh report be furnished by the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P., dealing with the objections of the applicant, before the next by E-Mail at JUDICIAL-NGT@GOV.IN Preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List again on 06.10.2020

मा0 न्यायालय के आदेशों के क्रम में SIEAA द्वारा अपने आदेश संख्या-400/पर्या0/ए0ई0आई0ए0ए0/90/2020 दिनांक 28.09.2020 द्वारा पूर्व में श्री मेराज उद्दीन सदस्य एस0ई0ए0सी0 तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) द्वारा याची की आपत्ति दिनांक 22.08.2020 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। संलग्नक-1

उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय सहारनपुर के पत्र संख्या-5320/ए0सी0/2020-21 दिनांक 20.11.2020 द्वारा याची श्री प्रमोद कुमार को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु दिनांक 24.11.2020 के पूर्वान्ह 11:00 बजे नियत की गयी थी, परन्तु याची निर्धारित तिथि व समय पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ। निर्धारित समय पर उनके प्रतिनिधि श्री अजेश कुमार शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा पुनः 22.08.2020 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन की प्रति प्रस्तुत की गयी है। तदोपरान्त याची की आपत्ति दिनांक 22.08.2020 में इंगित बिन्दु पर विचार किया गया। याची प्रमोद द्वारा अपनी आपत्ति में मुख्य रूप से निम्न आपत्ति व्यक्त की गयी है:-

- 1- District Survey Report (DSR) नोटिफिकेशन दिनांक 15.01.2016 के व उसके परिशिष्ट 10 व 11 के व गाईड लाईन्स 2016 के अनुसार नहीं है। DSR से पूर्व या ई0सी0 से पूर्व आज तक कोई Replenishment study नहीं की गई व न ही करायी गई है। सभी खनन पट्टे, गाईड लाईन्स 2020 के बाद ग्रान्ट किये गये है।
- 2- हथनी कुण्ड बैराज के अपरस्ट्रीम में एफ0आर0आई0 की रिपोर्ट जो मा0 एन0जी0टी0 द्वारा स्वीकार की गई तो भी उस प्रतिबाधित क्षेत्र में खनन अनुमति 3 लॉट में दी गई।
- 3- नेशनल पार्क व हाथी रिजर्व की दूरियों छुपाकर प्रतिबाधित एरियाओं में खनन की अनुमति दी गई जिसमें वन विभाग की भी मिलिभगत थी।
- 4- सभी लॉट कलस्टर में है लेकिन प्रमाण पत्र तथ्यों को छिपाकर गलत दिया गया कोई EIA/EMP कलस्टर की नहीं करायी गई।



- 5- जिला सहारनपुर में लगातार सरकारी विभाग के मिलिभगत से अवैध खनन हुआ है व भारी पर्यावरण क्षति पहुँची है बिना किसी क्षति पूर्ति किये हुए पुनः खनन कराया जा रहा है लॉक डाउन में अवैध खनन हुआ है।
- 6- लॉट नं०-03 रहना में बिना ई०सी० के खनन शुरू कराया गया। ई०सी० एवं टोर गलत जारी किये गये है मा० एन०जी०टी० के आदेशों की अवहेलना की गई है।
- 7- मा० कमेटी द्वारा रिपोर्ट गलत दी गई है कोई जॉच मौके पर नहीं की गई है दोनों ही सदस्य मा० एन०जी०टी० ने अधिकृत नहीं किया है एक सदस्य SEAC का है और दूसरा जिला प्रशासन अधिकारी है एक ई०सी० जारी करने वाली मा० कमेटी के सदस्य है और दूसरे सदस्य के द्वारा DSR में अवैध संशोधन कर खनन पट्टे स्वीकृत किये गये है दोनों सम्बन्धित है सम्बन्धित व्यक्ति कभी जॉच अधिकारी नहीं हो सकते है।

याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2020 में उपरोक्त 7 बिन्दुओं पर आपत्ति प्रस्तुत किया गया है। जिसका बिन्दुवार आख्या प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नांकित तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना उचित है। ओ०ए० 184/2013 गुरुप्रीत सिंह बग्गा बनाम एम०ओ०ई०एफ० बनाम उ०प्र० सरकार में पारित आदेश दिनांक 08.08.2018 के पैरा-2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि:-

A status report has been filed before this Tribunal by Ministry of Environment, Forest and Climate change on 15-09-2016 along with the report of High Powered Committee dated 19-05-2016. Recommendations in the High Powered Committee Report are that mining should be done in terms of the Mining Plan. Since in Saharanpur the investigation had not been completed, no mining should be permitted. Mining should be only after valid consent to operate and subject to compliance of the environmental clearance conditions which are to be enforced by the DEIAA, SPCB and Regional Offices of MoEF &CC. There should be quarterly meeting of District Level Task Forces for inter-state co-ordination. Recommendations have also been made for operating the check posts and recovery of ecological compensation.

Submission has also been filed by the State of Uttar Pradesh stating that the State has submitted approved Comprehensive mining plan for Saharanpur on 30-08-2017 which calls for lifting of the complete ban. The State of UP had submitted a mining plan to the MoEF & CC and the same has been filed before this Tribunal on 30-08-2017.

An affidavit has also been filed by MoEF & CC on 31-08-2017, in response to the order of this Tribunal dated 18-07-2017. According to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the mining plans of Saharanpur district have been duly approved by the State Mining and Geology Department of Uttar Pradesh. The HPC has concurred with the same.

In view of the above, we make it clear that the order of this Tribunal dated 18-02-2016 will not be a bar to mining in the District of Saharanpur in accordance with the conditions of the said order and consistent with the environmental laws. संलग्नक-2

इस प्रकार जिला सहारनपुर का सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2017 का Approved Comprehensive Mining Plan मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली द्वारा स्वीकार करते हुए खनन पर लगाई गई रोक को हटा लिया गया है। Approved Comprehensive Mining Plan में उल्लेखित क्षेत्रों को जनपद सहारनपुर का जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर आपत्ति एवं सुझाव हेतु कार्यालय के पत्र संख्या-3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 कलक्टेक्ट में इसकी एक प्रति रखते हुए नियमानुसार Public domain में 21 दिन हेतु रखा गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 02.12.2017 में उपलब्ध 37 क्षेत्रों में से 32 क्षेत्रों को छोड़ते हुए मात्र 5 क्षेत्रों जो हाईपावर कमेटी के रिपोर्ट से अच्छादित न होने के कारण शासनादेश संख्या-1954/86-20007 दिनांक 12.08.2017 में दिए गए निर्देशों के क्रम में क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से 5 वर्षीय खनन पट्टा पर उठाये जाने हेतु कार्यालय विज्ञप्ति संख्या-88/खनिज/2017-18 दिनांक 20.01.2018 जारी की गई। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.2020 मे लिए गए निर्णय के अनुसार 5 नये क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया। जिसे कार्यालय के पत्र संख्या-1057/खनन/2019-20 दिनांक 07.09.2019 द्वारा 21 दिन हेतु आपत्ति एवं सुझाव हेतु Public domain में रखा गया। उक्त 5 नये क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से उठाये जाने हेतु कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या-1719/खनिज/2019-20 दिनांक 16.09.2019 एवं विज्ञप्ति संख्या-1959/खनिज /2019-20 दिनांक 01.11.2019 द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। स्वीकृत खनन क्षेत्र में SEIAA द्वारा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही पट्टा विलेख का निष्पादन कराया गया है साथ ही खनन की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित

Handwritten signature

अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनांक 08.08.2018 का समादर करते हुए जनपद सहारनपुर में खनन कार्य संचालित किया जा रहा है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में आख्या:-

यहाँ पर उल्लेखनीय है कि पूर्व में विज्ञापित क्षेत्र (क) यमुना नदी लाट संख्या-3 रहना 19.90 एकड़ में 04.04.2012 के पश्चात कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।

(ख) लाट संख्या-34 कालूवाला पहाड़ीपुर 46.32 एकड़ में 03.04.2012 के पश्चात कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।

(ग) यमुना नदी लाट संख्या-38 नुनयारी अहतमाल रकबा-60.00 एकड़ में भी 04.04.2012 के पश्चात कोई खनन कार्य नहीं हुआ है।

उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में लगभग 7-8 वर्ष से कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। अन्य 5 क्षेत्र विल्कुल नया है जिसमें कभी कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। जनपद सहारनपुर में यमुना नदी व अन्य सहायक नदियों शिवालिक पर्वत श्रृंखला के Foothill में पड़ता है। इतनी लम्बी अवधि तक कोई खनन न होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात बालू/बजरी/बोल्डर का जमाव होता रहा है। क्षेत्र में उपलब्ध खनिज एवं खनन योग्य मात्रा को ही विज्ञप्ति में शामिल किया गया है।

इस प्रकार शासनादेश दिनांक 12.08.2017 के अनुसार सम्पन्न ई-निविदा सह ई-नीलामी में उच्चतम ऑफरदाता को लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है:- **संलग्नक-3**

उपरोक्त से स्पष्ट है कि क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर क्षेत्र को विज्ञापित किया गया है जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उपलब्ध है। 7-8 वर्ष लम्बे अन्तराल के बाद ही क्षेत्र विज्ञापित किया गया है। इतनी लम्बी अवधि तक कोई खनन न होने से प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात बालू/बजरी/बोल्डर का जमाव हुआ है। क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की मात्रा एवं खनन योग्य मात्रा को ही विज्ञापित किया गया है। इस प्रकार सभी क्षेत्रों की विज्ञप्ति गार्ड लाईन 2020 जारी से पूर्व हुआ है तथा लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया है। इस प्रकार याची की आपत्ति निराधार है एवं विचार किये जाने योग्य नहीं है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में आख्या:-

प्रश्नगत रहना गाटा संख्या-03 क्षेत्र यमुना नदी में पड़ता है जो हथनीकुण्ड बैराज से 5.12 किमी० दूरी पर है। इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना भी कि फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहरादून द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक जनवरी 2017 इकोलॉजिकल डैमेज, असेसमन्ट एवं ईको फॉरेस्ट को प्रस्तुत की गई है, जिसके पृष्ठ संख्या-100 बिन्दु 7 की संस्तुति इस प्रकार है "The river tract upstream of Hathnikund Barrage is important for wild life and birds due to its wetland character and habitat contiguity with Kalesar National Park in Haryana and Shivalik hill forests in Uttarakhand/Uttar Pradesh. Therefore it is suggested and develop it as a wildlife habitat.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट (F.R.I) का उपर्युक्त परामर्श मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेंज को प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में MOEF अथवा माननीय न्यायालय अथवा शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में आख्या:-

ग्राम रहना गाटा संख्या-179/2 क्षेत्रफल-3.75 है० गेसराराव नदी में पड़ता है प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग के पत्र संख्या-31/14-1 सहारनपुर दिनांक 02.07.2019 द्वारा खनन क्षेत्र शेरपुर पेलों, मायापुर रूपपुर, रहना, हैदरपुर हिन्दुवाला की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की गयी है उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में प्रश्नगत रहना 179/2 प्रस्तावित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 2.80 कि०मी० तथा कालेशर नेशनल पार्क से 7.80 कि०मी० है। इस प्रकार याची द्वारा की गयी आपत्ति निराधार तथ्यों पर आधारित है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध में आख्या:-

जनपद में विज्ञापित क्षेत्रों में से मायापुर रूपपुर, हैदरपुर हिन्दुवाला, रहना-179/2, बरथा कोरसी, शेरपुर पेलों विल्कुल नये क्षेत्र है तथा रहना गाटा संख्या-3 व नुनियारी अहतमाल जो हाई पावर कमेटी की आख्या से अच्छादित नहीं थे। उन्ही क्षेत्रों की विज्ञप्ति जारी की गयी है तथा लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी किया गया है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 32 क्षेत्रों को अभी तक कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है ओर न अभी तक किसी को आवंटित किया गया है। अतः वर्तमान में उन 32 खनन पट्टा संचालित/कार्यरत न होने के कारण

शुभम

आख्या दी गई है। इस प्रकार कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। याची का कथन निराधार है एवं विचार किये जाने योग्य नहीं है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में आख्या:-

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर की जांच आख्या 27.02.2020 के क्रम में शासन के निर्देश पर अवैध खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जिनमें से तीन स्टोन क्रेशर स्वामियों का भण्डारण लाईसेंस निरस्त किया गया है। अन्य 7 अवैध खननकर्ता के विरुद्ध अवैध खनन पर देय स्वामित्व तथा अर्थदण्ड की वसूली की कार्यवाही की गई है। उक्त कार्यवाही लॉकडाउन की अवधि के पूर्व की है। अवैध खनन/परिवहन पर लगातार प्रवर्तन कार्य कराया गया है। इस प्रकार याची की आपत्ति निराधार है एवं विचार किये जाने योग्य नहीं है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-6 के सम्बन्ध में आख्या:-

लाट संख्या-3 ग्राम रहना का खनन पट्टा SEIAA के पत्र संख्या-134/पर्या/ SEIAA /4294/2018 दिनांक 18.06.2020 द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र संख्या-481/पर्या0/ SEIAA / 4294/2018 दिनांक 22.11.2018 में इंगित शर्तों के अधीन श्री सतेन्द्र कुमार के पक्ष में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र Transfer किया गया है। उक्त SEIAA का पत्र दिनांक 18.06.2020 प्राप्त होने के उपरान्त ही दिनांक 20. 06.2020 को पट्टा विलेख का निस्पादन कराया गया है तथा कार्यालय के पत्र संख्या-4317/2020-21 दिनांक 23.06.2020 द्वारा खनन कार्य की अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार याची की आपत्ति निराधार तथ्यों पर आधारित है जो विचार किये जाने योग्य नहीं है।

आपत्ति बिन्दु संख्या-7 के सम्बन्ध में आख्या:-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.06.2020 के अनुपालन में SEIAA के पत्र संख्या 171/पर्या/एस0ईआई0ए0ए0/90/2020 दिनांक 03.07.2020 द्वारा निम्नलिखित समिति का गठन किया गया है:-

1. श्री मेराजुद्दीन SEIAA द्वारा नामित सदस्य
2. जिलाधिकारी द्वारा नामित श्री विनोद कुमार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) सहारनपुर (संलग्नक-4)

इस प्रकार की याची की आपत्ति निराधार तथ्यों पर आधारित है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उठाये गये बिन्दुओं पर खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या

1- मायापुर रूपपुर (गाटा संख्या-14/1 रकबा 3.10हे0) बादशाहीबाग राव नदी

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01. 2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 द्वारा कलेक्टर सूचना पट पर लगाया गया एवं जिले की वेबसाइट पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया। (संलग्नक-05)
- उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, परन्तु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में गाटा संख्या संबंधी त्रुटि होने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 1964/डी0एस0आर0/ सहारनपुर (खनन)/2018 दिनांक 26.10.2018 द्वारा शुद्धि पत्र जारी किया गया। (संलग्नक-06)
- यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि पाँच नये क्षेत्र ग्राम शेरपुर पेलो, मायापुर रूपपुर, हैदरपुर हिन्दुवाला, रहना व बरथा कोरसी के संबंध में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.2019 द्वारा 05 नये क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया, जिसे कार्यालय पत्र संख्या 1051/खनन/2019-20 दिनांक 07.09.2019 द्वारा जिले के वेबसाइट पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु 21 दिन के लिए अपलोड किया गया। (संलग्नक-07)

सहारा

वि

- 5-
- आपत्ति हेतु निर्धारित 21 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ।
 - भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 के क्रम नामित कार्यदायी एजेन्सी (एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति संख्या 1719/खनिज/2019-20 दिनांक 16.09.2019 एवं विज्ञप्ति संख्या 1959/खनिज/2019-20 दिनांक 01.11.2019 को जारी किया गया।
 - एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 का पालन करते हुए उच्चतम बोलीदाता की सूचना ई-मेल के माध्यम से दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध करायी गई। (संलग्नक-08)
 - सम्यक विचारोपरान्त उच्चतम बोलीदाता श्री राजेश कुमार निवासी ग्राम गढी बीरबल इन्द्री जिला करनाल के पक्ष में दिनांक 28.12.2019 को लेटर ऑफ़ इन्टेंट (LOI) जारी किया गया है। तत्पश्चात SEIAA के पत्र संख्या 88/parya/SEIAA/5402/2019 दिनांक 27.05.2020 द्वारा E.C. प्राप्त होने एवं समस्त औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरान्त श्री राजेश कुमार के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 15.06.2020 को किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	District Survey report for river bed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020.	विषयगत खनन क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा जन सामान्य हेतु उपलब्ध कराये गये तथा DEIAA के द्वारा दिनांक 04.09.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 नये क्षेत्र शामिल किये गये थे जिसमें मायापुर रूपपुर भी शामिल था। तत्समय Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining 2020 प्रभाव में नहीं थी।
2	The mining sites are within 1 K.M. from Kalesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF & CC order dated 08.08.2019	प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग के पत्र संख्या 31/14-1 सहारनपुर दिनांक 02.07.2019 द्वारा खनन क्षेत्र शेरपुर पेलो, मायापुर रूपपुर, रहना, हैदरपुर हिन्दुवाला अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम मायापुर रूपपुर प्रस्तावित स्थल की आक्षरित वन क्षेत्र से दूरी 1.20 कि०मी० एवं कालेशर नेशनल पार्क से दूरी 15.70 कि०मी० है। (संलग्नक-9)
3	Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage is Saharanpur	प्रश्नगत मायापुर रूपपुर गाटा संख्या 14/1 रकबा 3.10हे० क्षेत्र बादशाही बाग राव नदी में पडता है जो यमुना नदी अथवा हथनीकुण्ड बैराज के अन्तर्गत नहीं आता है।
4	Cluster Impact Assessment has not been done as required.	मायापुर रूपपुर क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि के अर्न्तगत कोई भी अन्य क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है।
5	The sand mining has been continuing even during the	मायापुर रूपपुर का खनन पट्टा बादशाही बाग राव नदी में स्थित बालू, बजरी, बोल्डर (मिश्रित अवस्था में) स्वीकृत है

Handwritten signature

Handwritten mark

locked down period

जिसमें खनन कार्य लॉक डाउन की अवधि में नहीं हुआ है। दिनांक 15.06.2020 पट्टा अभिलेख का निष्पादन होने के उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ हुआ है।

2- रहना (गाटा संख्या-179/2 रकबा 3.75हे0) गैसरा रॉ नदी

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 द्वारा कलेक्ट्रेट सूचना पट पर लगाया गया एवं जिले की वेबसाईट पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया। (संलग्नक-05)
- उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, परन्तु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में गाटा संख्या संबंधी त्रुटि होने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 1964/डी0एस0आर0/सहारनपुर (खनन)/2018 दिनांक 26.10.2018 द्वारा उक्त शुद्धि पत्र जारी किया गया। (संलग्नक-06)
- यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि पॉच नये क्षेत्र ग्राम शेरपुर पेलो, मायापुर रूपपुर, हैदरपुर हिन्दुवाला, रहना व बरथा कोरसी के संबंध में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.2019 द्वारा 05 नये क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया, जिसे कार्यालय पत्र संख्या 1051/खनन/2019-20 दिनांक 07.09.2019 द्वारा जिले के वेबसाईट पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु 21 दिन के लिए अपलोड किया गया। (संलग्नक-07)
- आपत्ति हेतु निर्धारित 21 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ।
- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 के क्रम नामित कार्यदायी एजेन्सी (एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति संख्या 1719/खनिज/2019-20 दिनांक 16.09.2019 एवं विज्ञप्ति संख्या 1959/खनिज/2019-20 दिनांक 01.11.2019 को जारी किया गया।
- एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 का पालन करते हुए उच्चतम बोलीदाता की सूचना ई-मेल के माध्यम से दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध करायी गई। (संलग्नक-08)
- सम्यक विचारोपरान्त उच्चतम बोलीदाता श्री संजय भाटिया पुत्र स्व0 श्री आनन्द प्रकाश भाटिया निवासी 1/472 रामचन्द्रपुरी कुतुबशेर सहारनपुर के पक्ष में दिनांक 07.01.2020 को लेटर ऑफ़ इन्टेंट (LOI) जारी किया गया है। तत्पश्चात SEIAA के पत्र संख्या 87/parya/SEIAA/5402/2019 दिनांक 27.05.2020 द्वारा E.C. प्राप्त होने एवं समस्त औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरान्त श्री संजय भाटिया के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 06.06.2020 को किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	District Survey report for river bed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as	विषयगत खनन क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 के

Handwritten signature

Handwritten mark

	required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020.	द्वारा जन सामान्य हेतु उपलब्ध कराये गये तथा DEIAA के द्वारा दिनांक 04.09.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 नये क्षेत्र शामिल किये गये थे जिसमें रहना भी शामिल था। तत्समय Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining 2020 प्रभाव में नहीं थी।
2	The mining sites are within 1 K.M. from Kalesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF & CC order dated 08.08.2019	प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग के पत्र संख्या 31/14-1 सहारनपुर दिनांक 02.07.2019 द्वारा खनन क्षेत्र शेरपुर पेला, मायापुर रूपपुर, रहना, हैदरपुर हिन्दुवाला अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम रहना प्रस्तावित स्थल की आक्षरित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 2.80 कि०मी० एवं कालेशर नेशनल पार्क से दूरी 7.80 कि०मी० है। (संलग्नक-9)
3	Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage is Saharanpur	प्रश्नगत रहना गाटा संख्या 179/2 रकबा 3.75हे० क्षेत्र गैसरा रॉ नदी में पडता है जो यमुना नदी अथवा हथनीकुण्ड बैराज के अन्तर्गत नहीं आता है।
4	Cluster Impact Assessment has not been done as required.	रहना क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई भी अन्य क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है।
5	The sand mining has been continuing even during the locked down period	रहना का खनन पट्टा गैसरा रॉ नदी में स्थित बालू, बजरी, बोल्टर (मिश्रित अवस्था में) स्वीकृत है जिसमें खनन कार्य लॉक डाउन की अवधि में नहीं हुआ है। दिनांक 06.06.2020 पट्टा अभिलेख का निष्पादन होने के उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ हुआ है।

3- रहना (लॉट संख्या-3 गाटा संख्या-3 रकबा-8.05हे०) यमुना नदी

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 द्वारा कलेक्टर सूचना पट पर लगाया गया एवं जिले की वेबसाईट पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया। (संलग्नक-05)
- उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, परन्तु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में गाटा संख्या संबंधी त्रुटि होने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 1964/डी०एस०आर०/सहारनपुर (खनन)/2018 दिनांक 26.10.2018 द्वारा उक्त शुद्धि पत्र जारी किया गया। (संलग्नक-06)
- आपत्ति हेतु निर्धारित 21 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय, सहारनपुर को प्राप्त नहीं हुआ।
- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 के क्रम नामित कार्यदायी एजेन्सी (एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति संख्या 88/खनिज/2017-18 दिनांक 20.01.2018 को जारी किया गया।
- एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 का पालन करते हुए उच्चतम बोलीदाता की सूचना ई-मेल के माध्यम से दिनांक 09.03.2018 को उपलब्ध करायी गई। सम्यक विचारोपरान्त कार्यालय के पत्र संख्या-423/खनिज/2017-18 दिनांक 15.03.2018 द्वारा लेटर ऑफ इण्टेंट जारी किया गया।

Handwritten signature

Handwritten mark

उच्चतम बोलीदाता श्री राहुल पंवार द्वारा SEIAA के पत्र संख्या 481/parya/SEAC-4294/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा ई0सी0 प्राप्त किया गया परन्तु पट्टा विलेख का निष्पादन न करने के कारण जिलाधिकारी सहारनपुर के कार्यालय आदेश संख्या-2623/ख0अनु0/ई-नीलामी/सहारनपुर दिनांक 08.02.2019 को स्वीकृत लेटर ऑफ इण्टेंट निरस्त किया गया।

- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 के क्रम में नामित कार्यदायी एजेन्सी (एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम) को अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त पुनः रहना लॉट संख्या -3 का ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति संख्या 1719/खनिज/2019-20 दिनांक 16.09.2019 एवं विज्ञप्ति संख्या 1959/खनिज/2019-20 दिनांक 01.11.2019 को किया गया।
- एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 का पालन करते हुए उच्चतम बोलीदाता की सूचना ई-मेल के माध्यम से दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध करायी।
- सम्यक विचारोपरान्त उच्चतम बोलीदाता श्री सत्येन्द्र कुमार पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह निवासी खैरा नजफगढ नई दिल्ली के पक्ष में दिनांक 23.01.2020 को लेटर आफ इण्टेंट (LOI) जारी किया गया है। तत्पश्चात SEIAA के पत्र संख्या 134/parya/SEAC/4294/2018 दिनांक 18.06.2020 द्वारा E.C. प्राप्त होने एवं समस्त औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करने के उपरान्त श्री सत्येन्द्र कुमार के पक्ष में पट्टा विलेख का निष्पादन दिनांक 20.06.2020 को किया गया।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	District Survey report for river bed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020.	विषयगत खनन क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा जन सामान्य हेतु उपलब्ध कराये गये निर्धारित अवधि में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए। तत्समय Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining 2020 प्रभाव में नहीं थी।
2	The mining sites are within 1 K.M. from Kalesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF & CC order dated 08.08.2019	भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या SO 1485 (E) दिनांक 22.04.2016 (संलग्नक-10) के पैरा-1(2) में कलेसर नेशनल पार्क एवं वाईड लाइफ सेन्चुरी का कॉआर्डिनेट्स दिया गया है तथा 1(5) में ईको सेन्सिटिव जोन में पड़ने वाले 31 ग्रामों का नाम दिया गया है, जिसमें रहना अथवा कोई भी ग्राम जनपद सहारनपुर का नहीं है।
3	Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage in Saharanpur	प्रश्नगत रहना लॉट संख्या-3 गाटा संख्या-3 क्षेत्र यमुना नदी में पडता है जो हथनीकुण्ड बैराज से 5.12 किमी0 की दूरी पर है। इसके अतिरिक्त यह अवगत कराना भी कि फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट देहरादून द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक जनवरी 2017 इकोलॉजिकल डैमेज, असेसमेन्ट एवं ईको फारेस्ट प्लान की संस्तुति मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट को प्रस्तुत की गई है, जिसके पृष्ठ संख्या 100 बिन्दु 7 की संस्तुति इस प्रकार है "The river tract

Atucom

		<p>upstream of Hathnikund Barrage is important for wild life and birds due to its wetland character and habitat contiguity with Kalesar National Park in Haryana and Shivalik hill forests in Uttarakhand/Uttar Pradesh. Therefore it is suggested to close it altogether from mining activities and develop it as a wildlife habitat.</p> <p>इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट (F.R.I) का उपर्युक्त परामर्श मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एण्ड क्लाइमेट चेंज को प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय अथवा शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ।</p>
4	Cluster Impact Assessment has not been done as required.	रहना लॉट संख्या-3 क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि के अर्न्तगत कोई भी अन्य क्षेत्र का खनन पट्टा स्वीकृत अथवा संचालित नहीं है।
5	The sand mining has been continuing even during the locked down period	रहना का खनन पट्टा यमुना नदी में स्थित बालू, बजरी, बोल्टर (मिश्रित अवस्था में) स्वीकृत है जिसमें खनन कार्य लॉक डाउन की अवधि में नहीं हुआ है। दिनांक 20.06.2020 पट्टा अभिलेख का निष्पादन होने के उपरान्त खनन कार्य प्रारम्भ हुआ है।

4- बरथाकोरसी (गाटा संख्या 01 रकबा 36.00हे0) यमुना नदी

- भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 द्वारा कलेक्टर सूचना पट पर लगाया गया एवं जिले की वेबसाइट पर आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से 21 दिन हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया। (संलग्नक-05)
- उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए, परन्तु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में गाटा संख्या संबंधी त्रुटि होने के कारण कार्यालय के पत्र संख्या 1964/डी0एस0आर0/सहारनपुर (खनन)/2018 दिनांक 26.10.2018 द्वारा उक्त शुद्धि पत्र जारी किया गया। (संलग्नक-06)
- यहाँ यह भी अवगत कराना समीचीन होगा कि पाँच नये क्षेत्र ग्राम शेरपुर पेलो, मायापुर रूपपुर, हैदरपुर हिन्दुवाला, रहना व बरथा कोरसी के संबंध में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.2019 द्वारा 05 नये क्षेत्र को सम्मिलित करने हेतु समिति द्वारा निर्णय लिया गया, जिसे कार्यालय पत्र संख्या 1051/खनन/2019-20 दिनांक 07.09.2019 द्वारा जिले के वेबसाइट पर आपत्ति एवं सुझाव हेतु 21 दिन के लिए अपलोड किया गया। (संलग्नक-07)
- आपत्ति हेतु निर्धारित 21 दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी कोई आपत्ति/सुझाव किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ।
- भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 के क्रम नामित कार्यदायी एजेन्सी (एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना विज्ञप्ति संख्या 1719/खनिज/2019-20 दिनांक 16.09.2019 एवं विज्ञप्ति संख्या 1959/खनिज/2019-20 दिनांक 01.11.2019 को जारी किया गया।

Handwritten signature

Handwritten mark

- एमएसटीसी-भारत सरकार का उपक्रम द्वारा शासनादेश संख्या 1875/86-2017 दिनांक 14.08.2017 का पालन करते हुए उच्चतम बोलीदाता की सूचना ई-मेल के माध्यम से दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध करायी गई। (संलग्नक-08)
- सम्यक विचारोपरान्त उच्चतम बोलीदाता श्री दीपक चौधरी प्रो० स्टार माईनस हकीकत नगर सहारनपुर के पक्ष में दिनांक 30.12.2019 को लेटर ऑफ़ इन्टेंट (LOI) जारी किया गया है। तत्पश्चात SEIAA से E.C. अपेक्षित है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में आख्या

क्र०सं०	बिन्दु	आख्या
1	2	3
1	District Survey report for river bed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020.	विषयगत खनन क्षेत्र में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी, सहारनपुर के पत्र संख्या 3968/खनन/2017-18 दिनांक 02.12.2017 के द्वारा जन सामान्य हेतु उपलब्ध कराये गये तथा DEIAA के द्वारा दिनांक 04.09.2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 5 नये क्षेत्र शामिल किये गये थे जिसमें बरथाकोरसी भी शामिल था। तत्समय Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining 2020 प्रभाव में नहीं थी।
2	The mining sites are within 1 K.M. from Kalesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF & CC order dated 08.08.2019	प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग के पत्र संख्या 4299/14-1 सहारनपुर दिनांक 17.06.2019 द्वारा खनन क्षेत्र बरथाकोरसी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम बरथाकोरसी प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम बरथाकोरसी गाटा संख्या-1 की जी०पी०एस० रिडिंग A- N30° 14' 37.1" E77° 31' 40.8" है। जी०पी०एस० रिडिंग से खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी 13.30 किमी० है। इसी प्रकार कालेशर नेशनल पार्क की जी०पी०एस० रिडिंग A- N30° 18' 44.00" E77° 34' 26.9" है। जी०पी०एस० रिडिंग के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान से खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी 8.83 कि०मी० है। (संलग्नक-11)
3	Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage is Saharanpur	प्रश्नगत बरथाकोरसी गाटा संख्या 01 रकबा 36.00हे० क्षेत्र यमुना नदी में पडता है। हथनीकुण्ड बैराज से डाउन स्ट्रीम में स्थित है।
4	Cluster Impact Assessment has not been done as required.	बरथाकोरसी जिसका उच्चतम ऑफरदाता के पक्ष में लेटर ऑफ़ इन्टेंट दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया (संलग्नक-12)। क्लस्टर प्रमाण पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश की सीमा में 500 मीटर की परिधि के अन्तर्गत कोई अन्य क्षेत्र, खनन पट्टा स्वीकृत एवं संचालित नहीं है। जहां तक हरियाणा राज्य के खनन पट्टा क्षेत्र का सम्बन्ध है, हरियाणा राज्य के जिला यमुनानगर के डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (DSR) के अनुसार बेलगढ क्षेत्र का कोई जियो कॉर्डिनेटस का उल्लेख नहीं है (संलग्नक-13)। यमुनानगर

24/10/24

24

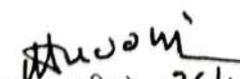
		के बेलगढ सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत खनन क्षेत्र ग्राम बेलगढ साउथ जिसका स्टेट एन्वायरमेंट इम्पैक्ट एस्समेंट अथोरिटी ऑफ हरियाणा के पत्र SEIAA/HR/2016/475 दिनांक 27.06.2016 (संलग्नक-14) द्वारा E.C. जारी किया गया है, जिसमें क्षेत्र के तीन कॉर्डिनेट्स दिये गये हैं:- A- N30° 13' 29.01" E77° 30' 34.59" B- N30° 13' 10.29" E77° 30' 24.22" C- N30° 12' 41.01" E77° 30' 17.97" उक्त क्षेत्र जनपद सहारनपुर के स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र बरथाकोरसी से न्यूनतम 1.4 किमी० से अधिक दूरी पर स्थित है। गुगल मानचित्र (संलग्नक-15)
5	The sand mining has been continuing even during the locked down period	बरथाकोरसी का खनन पट्टा यमुना नदी में स्थित बालू बजरी, बोलडर (मिश्रित अवस्था में) स्वीकृत है SEIAA से ई०सी० प्राप्त न होने के कारण अभी कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः खनन कार्य लॉक डाउन की अवधि में होने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

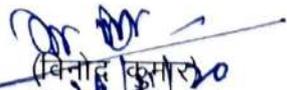
यहाँ पर माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी संज्ञान में लाना है कि याची द्वारा "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" 2020 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट तैयार करने का उल्लेख किया गया है।

जिसके संबंध में सादर संज्ञानित करना है कि उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 865/86/2020-01(सा०)/2020 दिनांक 12.06.2020 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" 2020 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट Modification (सुधार) के संबंध में निर्देश दिये गये हैं (संलग्नक-16)। शासनादेश दिनांक 12.06.2020 जारी होने के उपरान्त जनपद सहारनपुर में ई-निविदा सह ई-नीलामी संबंधी कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं हुयी है।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संज्ञान में समर्पित करना है कि जनपद सहारनपुर में बालू के दो खनन पट्टे तहसील सदर अन्तर्गत दरियाबरामद दिनांक 04.10.2019 से 03.10.2024 तक स्वीकृत है एवं तहसील नकुड स्थित ग्राम ढिक्काकलां दिनांक 16.11.2019 से 15.11.2024 तक स्वीकृत है। जिसमें बालू का खनन कार्य पट्टा विलेख के निष्पादन से प्रारम्भ है। दिनांक 23.03.2020 से सम्पूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन प्रारम्भ हुआ था, जिसके कारण दिनांक 23.03.2020 से खनन सक्रिया बन्द हो गयी थी। लॉकडाउन की अवधि के दौरान जनपद सहारनपुर में कोई खनन सम्बन्धी कार्य नहीं हुआ है। शासन के पत्र संख्या 5जी०आई०/86-2020-14 (सामान्य)/2020 दिनांक 17.04.2020 कुछ शर्तों के साथ खनन कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश प्राप्त हुआ (संलग्नक -17)। शासन के उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या 3909/ख०अनु०/खनन लिपिक/2020 दिनांक 05.05.2020 से शासनादेशों में इंगित शर्तों के अन्तर्गत खनन कार्य प्रारम्भ किया गया। (संलग्नक-18)

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 22.08.2020 निराधार तथ्यों पर आधारित होने के कारण विचार योग्य नहीं है अतः प्रश्नगत याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।


(मेराज उद्दीन) 24/11/2020
SEIAA
द्वारा नामित सदस्य


(विनोद कुमार)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
जिलाधिकारी, सहारनपुर
द्वारा नामित सदस्य

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : doeuplko@yahoo.com

Website : www.seiaaup.com

पत्रांक : 171/पर्या0 / एस0ई0आई0ए0ए0/90/2020

दिनांक 23 सितम्बर, 2020

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में ओ0 ए0 संख्या-90/2020 प्रमोद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में दिनांक 17.08.2020 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

1. Grievance in this application is inter - alia is against District Survey report for riverbed sand mining in District Saharanpur which is said to be without conducting replenishment study as required under the Sand Mining Management Guidelines, 2020. The mining sites are within 1 k.m. from Katesar National Park and U.P. Elephant Reserve which is prohibited as per MoEF&CC order dated 08.08.2019. Mining is also in prohibited area being upstream of Hathnikund Barrage in Saharanpur. Cluster Impact Assessment has not been done as required. The sand mining has been continuing even during the locked down period. The above report shows that there is noncompliance of the direction as the task has been assigned to the Technical Committee at the District level which does not comprise of experts. The micro assessment of the area is required to be done with the involvement of experts.
2. A report was sought from District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. vide order dated 29.06.2020
3. Accordingly, a report has been filed on 13.07.2020 to the effect that leases were granted prior to the Sustainable Sand Mining Guidelines, 2020. However, the fact remains that the replenishment study is required even de hors the said Guidelines, the objections of the applicant may be responded to by the Department. The applicant is at liberty to file a fresh representation before the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. within one week from today with reference to the report filed on 13.7.2020.
4. Let a fresh report be furnished by the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P., dealing with the objections of the applicant, before the next by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
List again on 06.10.2020

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 29.06.2020 के अनुपालन में एस0ई0आई0ए0ए0 द्वारा अपने कार्यालय-ज्ञाप संख्या-171, दिनांक 03.07.2020 के माध्यम से निम्नवत् समिति का गठन किया गया है:-

1. श्री मेराज उद्दीन, एस0ई0आई0ए0ए0 द्वारा नामित प्रतिनिधि।
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।

उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त अनुपालन आख्या, जो दिनांक 13.07.2020 को मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल की गयी। तदनुसार संयुक्त आख्या के विरुद्ध एवं मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2020 के क्रम में याची द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 22.08.2020 के सम्बन्ध में एस.ई.आई.ए.ए. द्वारा प्राधिकरण की बैठक, दिनांक 11.09.2020 में विचार-विमर्श कर प्रकरण को एस.ई.आई.सी. को कमेंट्स हेतु रिफरबैक किया गया, जिसपर समिति द्वारा बैठक दिनांक 25.09.2020 में विचार-विमर्श करते हुए निम्नवत् निर्णय लिया गया -

In view of above, the SEAC noted that as per letter no. 171/Parya/SEIAA/90/2020 dated 03/07/2020 to Member Secretary, SEIAA, U.P., the committee of Shri Meraj Uddin, nominated members of SEIAA and Shri Vinod Kumar, ADM (F&R) nominated member by District Magistrate, Saharanpur has already been constituted in this regard. The SEAC opined that the above joint committee

shall examine the objections raised by the applicant and will furnish a report within this month to SEIAA and District Magistrate, Saharanpur for filing before the Hon'ble NGT.

अतः उक्त निर्णय के क्रम में एस.ई.आई.ए.ए. एवं जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा पूर्व में गठित समिति एस0ई0आई0ए0ए0 द्वारा नामित प्रतिनिधि (श्री मेराज उद्दीन सदस्य, एस0ई0ए0सी0) तथा जिलाधिकारी, सहारनपुर द्वारा नामित प्रतिनिधि (श्री विनोद कुमार, अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व) द्वारा याची की आपत्ति दिनांक 22.08.2020 पर अपनी रिपोर्ट तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., उ0प्र0 एवं जिलाधिकारी, सहारनपुर को प्रस्तुत की जायेगी, जिससे ससमय मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, सहारनपुर।
2. अध्यक्ष, एस0ई0आई0ए0ए0, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, एस0ई0ए0सी0, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
4. श्री मेराज उद्दीन, सदस्य, एस0ई0ए0सी0।
5. जिला खनन अधिकारी, सहारनपुर।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Execution Application No. 17 of 2016
(M.A. NO. 723 OF 2016)

In
Original Application No. 184 OF 2013
AND

Original Application No. 171 of 2016
(M.A. NO. 528 OF 2016)

AND
Original Application No. 176 of 2016
(Earlier O.A. No. 184/2013)

(M.A. No. 1252 of 2017 & M.A. No. 1376 of 2017)

And
M.A. No. 425 of 2016

In
Original Application No. 184 of 2013

IN THE MATTER OF:

Pramod
(In Gurpreet Singh Bagga Vs. Ministry of Environment & Forest, & CC case)
Vs.

State of Uttar Pradesh & Ors. /
And
Pramod Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. /
And
Gurpreet Singh Bagga Vs. MoEF & Ors. /
And
Gurpreet Singh Bagga Vs. MoEF & Ors. /

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE DR. JUSTICE JAWAD RAHIM, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER

Present: Applicant: Mr. Alok Sangwan, Mr. Uttarakh Srivastava, Advs.
Respondents: Mr. Manish Kumar, Adv. for HP Govt.
Mr. Divya Prakash Pande, Adv. for MoEF
Mr. Divya Prakash Pande, Adv. for Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Mr. Om Prakash, Adv.
Mr. Anil Grover, AAG with Mr. Rahul Khurana & Mishal Vij, Advs. for State of Haryana and HSPCB
Mr. Ankit Verma, Adv. for State of Uttar Pradesh
Ms. Aishwarya Bhatti, AAG-UP

Date and Remarks	Orders of the Tribunal
Item Nos. 10 to 13 August 08, 2018 R	1. The matter of illegal mining in the flood plain of river Yamuna in the Districts of Yamuna Nagar, Haryana and Saharanpur, Uttar Pradesh was the subject matter of consideration by this Tribunal in judgment dated 18.02.2016. The Tribunal constituted a High Powered Committee headed by the Secretary, Ministry of Environment, Forest

Item Nos.
10 to 13

August 08,
2018

▪

and Climate Change with the representatives of the States of Haryana and Uttar Pradesh. The States were required to submit mining plan consistent with the statutory provisions indicating the methodology to be followed for permitting mining on the river bed and conditions required to be imposed. The plan way to provide for check posts to ensure that there is no illegal transportation of mined material. It was directed that the mining should be in a semi-mechanised and scientific manner or non-mechanised manner. It should be in an environment friendly manner. It was expected that a regulated regime will be brought about the illegal mining which had already taken place, direction to recover environment compensation was also issued. There was also a direction for investigation and enquiry as to who was responsible for illegal mining, apart from those identified in the proceedings before this Tribunal.

2. A status report has been filed before this Tribunal by Ministry of Environment, Forest and Climate Change on 15.09.2016 along with the report of High Powered Committee dated 19.05.2016. Recommendations in the High Powered Committee Report are that mining should be done in terms of the Mining Plan. Since in Saharanpur the investigation had not been completed, no mining should be permitted. Mining should be only after valid consent to operate and subject to compliance of the environmental clearance conditions which are to be enforced by the DEIAA, SPCB and Regional Offices of MoEF & CC. There should be quarterly meeting of District Level Task Forces for inter-state co-ordination. Recommendations have also been made for operating the

Item Nos.
10 to 13

August 08,
2018

check posts and recovery of ecological compensation.

Submission has also been filed by the State of Uttar Pradesh stating that the State has submitted approved comprehensive mining plan for Saharanpur on 30.08.2017 which calls for lifting of the complete ban. The State of UP had submitted a mining plan to the MoEF & CC and the same has been filed before this Tribunal on 30.08.2017.

An affidavit has also been filed by MoEF & CC on 31.08.2017, in response to the order of this Tribunal dated 18.07.2017. According to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, the mining plans of Saharanpur district have been duly approved by the State Mining and Geology Department of Uttar Pradesh. The HPC has concurred with the same.

In view of the above, we make it clear that the order of this Tribunal dated 18.02.2016 will not be a bar to mining in the District of Saharanpur in accordance with the conditions of the said order and consistent with the environmental laws. Whether or not the plan prepared for district Saharanpur is in accordance with the judgment or the environment laws is a subject matter which can be gone into in any appropriate proceedings, if raised.

It is submitted on behalf of State of Uttar Pradesh that in pursuance of the order of this Tribunal dated 18.02.2016, a report of assessment of the value of ecological damage has been made. Since there is no objection to the report, the report will stand accepted. Appropriate action may accordingly be taken in terms of the said report by the concerned authority.

Item Nos.
10 to 13

August 08,
2018

R

The matter stands accordingly disposed of.

....., CP
(Adarsh Kumar Goel)

....., JM
(Dr. Jawad Rahim)

....., JM
(S.P. Wangdi)

....., EM
(Dr. Nagin Nanda)

08.08.2018



जनपद सहारनपुर में बालू/बजरी/बोल्डर(मिश्रित अवस्था में) स्वीकृत/संचालित खनन पट्टा क्षेत्रों की अद्यवधिक स्थिति:-

क्र० सं०	तहसील	खनिज नाम	का	क्षेत्र का नाम	गाटा सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	उपखनिज की मात्रा (घ०मी० में)	विज्ञप्ति दिनांक	LOI का दिनांक	मार्डनिंग प्लान अनुमोदन का दिनांक	EC जारी का दिनांक	पट्टा निष्पादन/पट्टा अवधि	अभ्युक्ति
1	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		मायापुर रूपपुर	14/1	3.10	69,750	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	28.12.2019	14.01.2020	27.05.2020	15.06.2020 से 14.06.2025 तक	कार्यरत
2	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		रहना	179/2	3.75	67,500	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	07.01.2020	24.01.2020	27.05.2020	06.06.2020 से 05.06.2025 तक	कार्यरत
3	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		रहना ताट नं० 3	3 लॉट सं०-3	8.05	1,38,462	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	23.01.2020	13.03.2020	18.06.2020	20.06.2020 से 19.06.2025 तक	कार्यरत
4	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		हैदरपुर हिन्दुवाला	8/1, 19, 22	4.20	94,500	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	14.01.2020	26.02.2020	24.08.2020	06.10.2020 से 05.10.2025 तक	कार्यरत
5	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		शेरपुर पेलों	378/2, 379/2	7.00	1,97,500	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	14.01.2020	13.03.2020	-	-	EC प्राप्त करने हेतु SIEAA में लब्धित है।
6	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		बरथा कोरसी	1	36.00	7,56,000	16.09.2019 एवं पुनः 01.11.2019	30.12.2019	13.03.2020	-	-	EC प्राप्त करने हेतु SIEAA में लब्धित है।
7	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		काठवाला पहाड़ीपुर	92, 93 94, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 192/1 लॉट सं० 34	18.75	3,37,955	20.01.2018	15.03.2018	-	-	-	EC प्राप्त करने हेतु SIEAA में लब्धित है।
8	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		नुनियाशी अहतमाल	1/1/1 लॉट सं०-38	24.29	4,37,247	20.01.2018	15.03.2018	03.05.2019	22.11.2018	07.02.2019 से 06.02.2024 तक	दिनांक 18.12.2019 को निरस्त 2019 को निरस्त
9	बेहट	बालू/बजरी/बोल्डर		नुनियाशी अहतमाल	1/1/1 लॉट सं०-38	24.29	4,37,247	04.03.2020	05.06.2020	11.08.2020	-	-	EC प्राप्त करने हेतु SIEAA में लब्धित है।

नोट:- कम संख्या-8 पर अंकित क्षेत्र नुनियाशी अहतमाल की देय किस्त जमा न होने के कारण दिनांक 18.12.2019 को निरस्त किया गया है तथा दिनांक 04.03.2020 को पुनः विज्ञापित किया गया है।

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vincent Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : doeuplko@yahoo.com

Website : www.seiaaup.in

पत्रांक : 171 / पर्या0 / एस0ई0आई0ए0ए0 / 90 / 2020

दिनांक 03 जुलाई, 2020

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में ओ0 ए0 संख्या-90/2020 प्रमोद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 29.06.2020 को आदेश पारित किया गया है, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

... "We are of the view that a factual report needs to be called for in response to the above from a joint Committee comprising District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. which may be furnished before the next date by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. The Nodal Agency will be SEIAA, U.P. for coordination and compliance.

A copy of this order be sent to the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. by e-mail for compliance.

The applicant may serve a set of papers to the District Magistrate, Saharanpur and SEIAA, U.P. and file an affidavit of service by email by 03.07.2020.

List for further consideration on 15.07.2020."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश द्वारा निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री मेराज उद्दीन, -एस0ई0आई0ए0ए0 द्वारा नामित प्रतिनिधि * --- अध्यक्ष
2. जिलाधिकारी, सहारनपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि --- सदस्य

मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 29.06.2020 के अनुक्रम में कार्यवाही कर, रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर जमा की जायेगी।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

पुष्ठाकन सं0: 171 / पर्या0 / एस0ई0आई0ए0ए0 / 90 / 2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, भूतत्व एव खनिकर्म विभाग।
2. जिलाधिकारी, जनपद- सहारनपुर उ0प्र0।
3. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, एस0ई0आई0ए0ए0, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. अध्यक्ष, एस0ई0ए0सी0, विनीत खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. श्री मेराज उद्दीन, सदस्य एस0ई0ए0सी0।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव,
एस0ई0आई0ए0ए0

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर

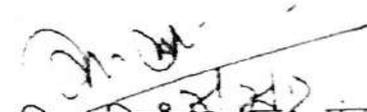
(खनन अनुभाग)

ख्या- 3258/खनन /2017-18

दिनांक:- 2 दिसम्बर 2017

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,
सहारनपुर नगर।

भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 1501.2016 के क0आ0.141(अ) के अनुरूप परिशिष्ट 10 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार कर कोलेक्टोरेट में इसकी एक प्रति रखते हुए पब्लिक डोमेन में रखा गया है। पब्लिक डोमेन हेतु जिले की वेबसाइट पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें जिससे की 21 दिनों में प्राप्त की जाने वाली टिप्पणी पर विचार करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा सके।


अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0) /
प्रभारी अधिकारी खनन,
सहारनपुर

व/क

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ, को सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय खनिज भवन लखनऊ को डी0एस0आर0 की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

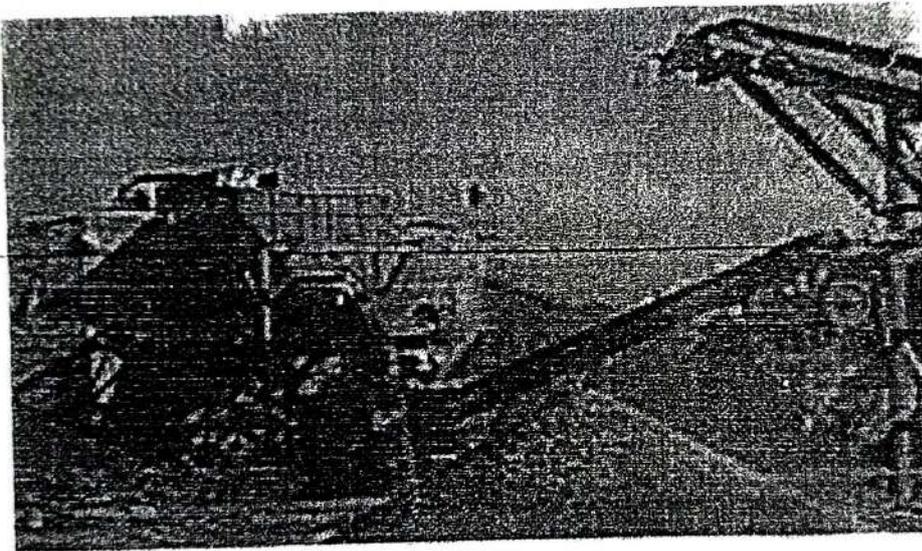

अपर जिलाधिकारी (वि0 एवं रा0),
प्रभारी अधिकारी खनन
सहारनपुर

व/क



DISTRICT SURVEY REPORT SAHARANPUR

AS PER NOTIFICATION MINISTRY OF ENVIORNMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NEW DELHI, 15TH JANUARY, 2016 NO. S.O. 141(E).



Mines Officer
Saharanpur
Member Secretary (DEAC)

Ex. Engr. Irrigation
Saharanpur
Chairman (DEAC)

S.D.M(Sadar)
Saharanpur
Member Secretary(DEIAA)

D.F.O
Saharanpur
Member (DEIAA)

District Officer
Saharanpur
Chairman (DEIAA)

D.F.O
Sivalik Forest Div
Member (DEIAA)

INTRODUCTION

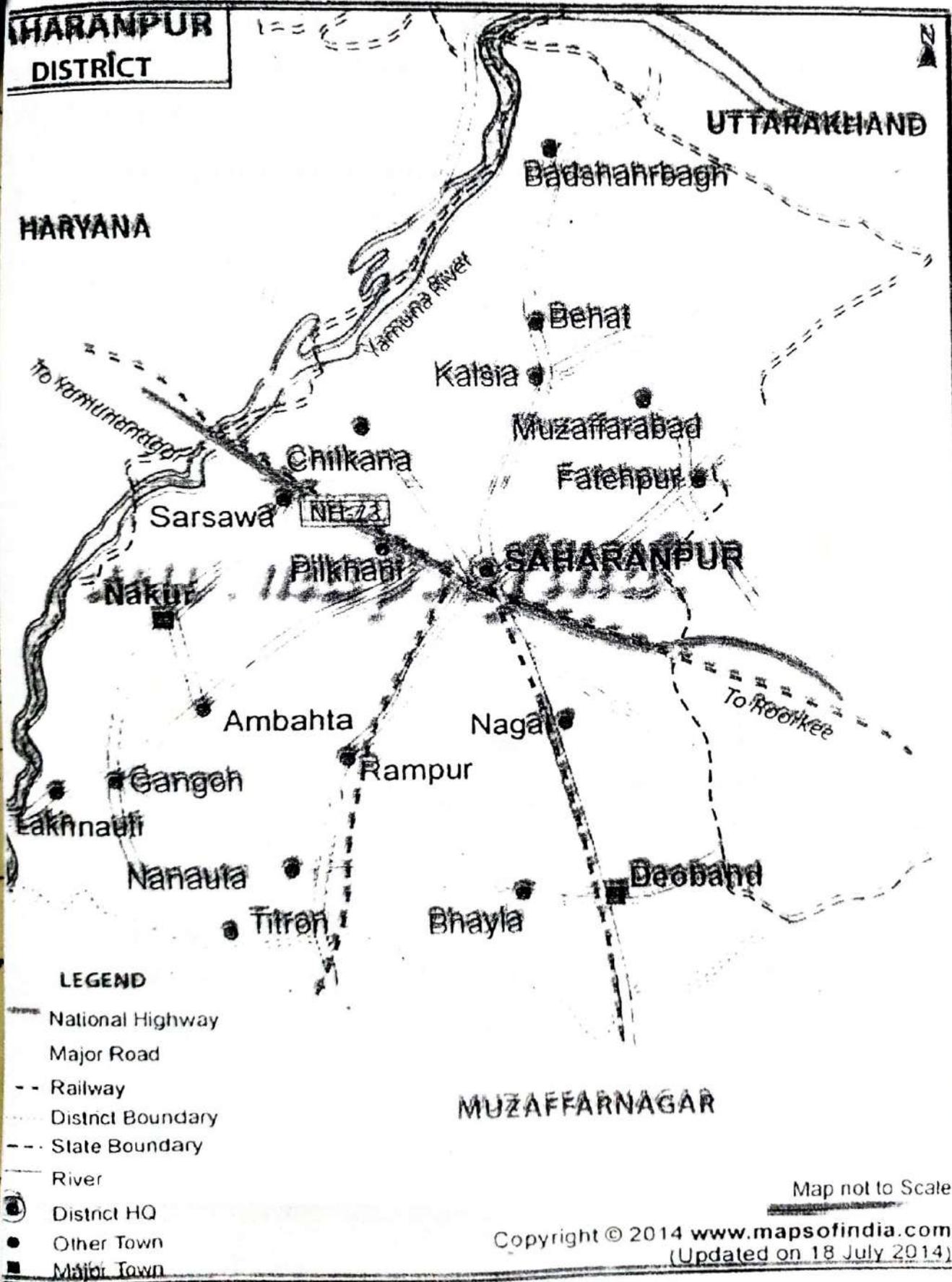
Ministry of Environment, forest and climate change, Government of India issued a gazette Notification No. S.O.141(E) dated 15-01-2016. In para 7(iii) of notification dated 15-01-2016 there is a provision for preparation of District Survey report for sand Mining or River Bed Mining and Mining of other Minor Minerals. The main objective of the preparation of District Survey Report (as per the sustainable sand Mining Guide Line) is to ensure Identification of areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structures and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in the area.

Saharanpur District in the northern most of the districts of Uttar Pradesh State, India. Bordering the State of Haryana, Himachal Pradesh and Uttarakhand and close to the foothills of shivalik range, it lies in the state of Uttar Pradesh. Saharanpur District forms part of Saharanpur Commissionary and it is commissionary Head Quarter. Pin code of Saharanpur is 247001. Saharanpur is famous in the World for its cottage industries, wood carving and historical heritage. Shakumbhari devi temple and Islamic education center Darul Ulum is famous in the World.

District Saharanpur lies in the extreme uppermost corner of Ganga Yamuna doab region. The District is bounded in west of river Yamuna & Haryana, Uttarakhand to the northern east and district Muzaffar Nagar and Shamli to its South. It extends from latitude $29^{\circ} 34'N$ - $30^{\circ}24'N$ Longitude $77^{\circ} 7'E$ - $78^{\circ} 12'E$ having an geographical area of 3860 Sq. Km.

District Saharanpur is well Connected with railway, Highways. Driving Distance between Saharanpur to India's capital New Delhi is 186 Km and aerial distance in 151 Km. Sarsawa Air port is in the district but it is not in commercial use. Jolly Grant Air Port in Uttarakhand is about 100 km from Saharanpur.

SAHARANPUR DISTRICT MAP



Geology of District Saharanpur

District Saharanpur lies in the extreme uppermost corner of Ganga Yamuna region. The district is bounded in west by river Yamuna & Haryana, Uttarakhand to the northeast and district Muzaffarnagar to its south. It extends in Latitude- $29^{\circ}24'$ N & Longitude- $77^{\circ}7'$ E- $78^{\circ}12'$ E having an geographical area of 3860 sq. km.

GEOLOGICAL & MINERAL MAP OF SAHARANPUR

SCALE 1:250,000



LEGEND

- | | |
|---|--|
|  Alluvium |  Bajri / Sand |
|  Sandstone |  Fault |

area is mostly covered by recent river filled sediments. Sandstone are used in the north eastern part. Yamuna fault is present in the north along the Yamuna River.

LOCAL GEOLOGY:

This region does not have much potential in mineral resources except river bed materials. Boulders of Limestone and sand stone found in the river bed are the primary main minerals. Limestone is found in the Shivalik hills. Stones are hard enough to be used for building purposes and are found in Shivaliks streams. The white efflorescence which is known by the name of Rah is found in the low lying tract and in the canal irrigated areas.

River Sand, Bajari and Boulders found in river bed is an alluvium deposited as a result of transportation of the same from the upstream side as far as 100 km from where the river originates and sediments are river borne and got deposited along course of river bed and side materials along its course. So, these sediments are river borne and got deposited along course of river bed and its flood plains with bigger sized fraction at the floor with graded and finer/smaller fractions as upper layers.

The sequences of formation observed with varying thickness are as follows:

- Silt (inseparable from main body of sand)
- Sand (1 mm to 3mm size)
- Bajri (3mm to 6mm size)
- Boulders (Large size)

The depth extension of deposit is more than 5 m. as judged from trial pit. The southern part of the district is flood plain area and mainly comprises of alluvial soil.

Major Rivers- Yamuna, Hindon & its tributaries.

Mining of sand, Bajari and Boulders is being done since long time. River borne sediments are deposited all along the river-bed and are very well exposed on the surface. Moreover, these sediments are accumulated/ replenished every year during rainy season by river-waters to almost equal to extracted level and sometimes more depending on the intensity of rains on the upstream side.

adequate quantity of sand, Bajari & Boulders in mixed state reserves are available. Since regular sand lifting is practiced along the river course, and more or less same level is seen after rains, so it is understood that sediments load carried is near equal to what is lifted.

GEO-TECHNICAL ASPECT:

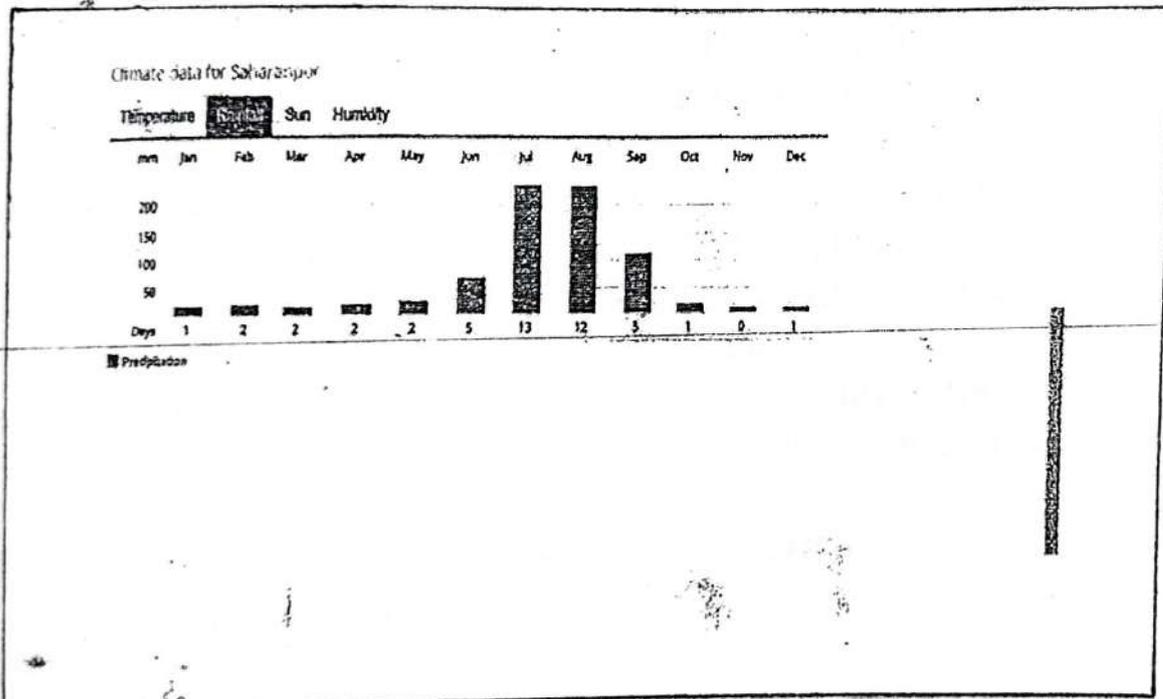
Structure of river bed and alluvial sand:-

The lease areas are allotted within the regular course of all 11 tributaries which are flooded in the rainy season. All the deposit comprises sand at upper most level. The sand is surrounded by boulders discoidal in shape having smooth surface. The thickness of deposit varies up to 5m from ground level.

During monsoon this bed replenished to large extent due to erosion by heavy flow in higher reach and as soon as the stream reaches in channel downward, shed their loads in river banks due to decrease in velocity and carrying capacity.

The area is dominated by medium to fine sand. geologically the area comprising of Terrace alluvium deposited in depositional terraces of old rivers the Alluvium may be differentiated into Older Alluvium consisting of oxidized (brown, yellow and khaki colour) sediments and Newer Alluvium comprising of un-oxidized (grey and khaki colour) sediments. The grains are sub-angular and the angularity of the grains of this category of sand decreases with depth.

AVERAGE RAIN FALL IN DISTRICT, SAHARANPUR



REVENUE & MINERAL PRODUCTION

The aim and object to carry-on mining operations within the region as well as in mining lots in the vicinity thereof happens to be imperative and unavoidable. According to experience and rough estimation of the District whatever quantity of minor minerals is extracted from the allotted lot during one year, part of the extracted quantity is automatically replenished every year by the River itself on account of its flow velocity and sediments brought along from upstream side. It is also submitted that if mining mineral is not at all effected in the region then the river-bed is likely to be raised in height with galloping speed leading to diluvium of river-banks and may lead to disturbance of environmental and ecological balance as well: where large areas of human habitation may become dangerously prone to inundation from river waters. Besides the above, the process mining of minor minerals (sand, bajri and boulders in mix state) is a constant source of revenue generation to the state government. It also not only ensures constant supply of building material for the development of society but also creates several opportunities of employment to the locals who are largely dependent on this activity.

Minerals- Only minor minerals viz. Sand, Bajri & Boulder are available in the river bed in district Saharanpur.

Mineral Based industries.

- (i) Stone crushers
- (ii) Screening plants

Last three years revenue of miner mineral in district saharanpur.

year	Revenue (In laks)
2014-15	1391.61
2015-16	952.93
2016-17	651.28
2017-18	810.00 (up to Nov, 2017)

POTENTIAL RIVER BED MINING AREA OF SAHARANPUR DISTRICT

The district Saharanpur is predominantly covered with river bed mineral viz, sand, bajari & boulders, along river Yamuna & its tributaries. Whole district can be divided in to there potential mining zones viz A, B and C. Zone B has two sub zones B1 and B2 and Zone C has there sub zones C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 and C8.

1- Details of the Potential mining area in Yamuna river in tabulated form.

Zone	Name of river	Tehsil	Location (Strech)	Area	Remarks
A	Yamuna	Behat	From Utrakhand boundary in upstream to Todarpurin downstream.	1670 Heactare	There is Hathinikund Barraje in Yamuna river. For the safety of the barraje all parameters needs to strictly follow.
B1,	Yamuna	Sadar	Govindpur in upstream to Holdapur in downstream.	209 Hectare	There is Ambala highway and railway track in between block B1 and B2 from which 1 km in upstream and 1 km in downstream has been excluded from the mining area.
B2	Yamuna	Nakur	From Jharoli in upstream to Dhika Khurd in downstream.	840 Hectare	
C1	Kothari Rao	Behat	Stretch along Kothari Rao river	107 Hectare	There is reserve forest in north of the C zone from which 5 km has been excluded from the mining area.
C2	Kaluwala	Behat	Streach along kaluwala river	130 Hectare	
C3	Solani	Behat	Stretch along Solani river	130 Hectare	
C4	Khairon Wali River	Behat	Stretch along Khairon wali river		
C5	Gaisra River	Behat	Stretch along Gaisra River		
C6	Badshahi bag Rao River	Behat	Stretch along Bhadsahibhag Rao River		
C7	Sahjahnpur Rao River	Behat	Stretch along Sahjahnpur Rao River		
C8	Lalo River	Behat	Stretch along Lalo River		

Mineral potential of the zone calculated on the basis of three meter depth of mineable mineral and the area for removal of mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

ZONE -A: A stretch along Yamuna river from north to south starting in upstream from Uttarakhand boundary to Todarpur in downstream. In west of this zone there is Yamuna Nagar, State of Haryana. The area of the zone is 1670 Hectare and river bed mineral found in this zone in the form of mixed state viz. Sand, Bajri and Boulder. The Zone lies in Tehsil Behat of district Saharanpur. Mineral potential of the zone is 300 lakh cubic meter which has been calculated on the basis of three meter depth of mineable mineral and the area for removal of mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone B:-

Zone-B1:- A stretch along Yamuna river from Govindpur in upstream to Holdapur in downstream. The area of the zone is 209 Hectare and river bed mineral found in this zone is Sand. The zone lies in Tehsil Sadar of district Saharanpur. Mineral potential of the zone is 37 lakh cubic meter which has been calculated on the basis of three-meter depth of mineable mineral and the area for removal of mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone- B2 :- A stretch along Yamuna river from Jharoli in upstream to Dhika Khurd in downstream. The area of the zone is 840 Hectare and river bed mineral found in this zone is Sand. The Zone lies in Tehsil Nakur of district Saharanpur. Mineral potential of the zone is 151 lakh cubic meter which has been calculated on the basis of three meter depth of mineable mineral and the area for removal of mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone C:-

Zone- C1:- A stretch along Kothari Rao/Hinden river. The area of the zone is 107 Hectare and river bed mineral found in the form of mixed state viz. Sand, Bajri and Boulder. The Zone lies in Tehsil Behat of district Saharanpur. Mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone- C2:- A stretch along Kaluwala river. The area of the zone is 130 Hectare and river bed mineral found in the form of mixed state viz. Sand, Bajri and Boulder. The zone lies in Tehsil Behat of district Saharanpur. Mineral potential of the zone is 23 lakh cubic meter which has been calculated on the basis of three meter depth of mineable mineral and the area for removal of mineral in a river to be 60 percent of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone-C3:- A stretch along Solani river. The area of the zone is 130 Hectare and river bed mineral found in the form of mixed state viz. Sand, Bajri and Boulder. The

Zone lies in Tehsil Behat of district Saharanpur. Mineral potential of the zone is 23 lakh cubic meter which has been calculated on the basis of three meter depth of the area as per the Ministry of Environment, Forest and Climate change, Government of India Guidelines of September, 2015.

Zone C4:- A stretch along Khairon Wali River. River bed mineral is found in mixed state viz Sand, Bazri and Bolder. Area lies in tehsil Behat.

Zone C5:- A stretch along Gaisra River. River bed mineral is found in mixed state viz Sand, Bazri and Bolder. Area lies in tehsil Behat.

Zone C6:- A stretch along Badshahi bag Rao River. River bed mineral is found in mixed state viz Sand, Bazri and Bolder. Area lies in tehsil Behat.

Zone C7:- A stretch along Sahjahnpur Rao River. River bed mineral is found mixed state viz Sand, Bazri and Bolder. Area lies in tehsil Behat.

Zone C8:- A stretch along Lalo River. River bed mineral is found in mixed state viz Sand, Bazri and Bolder. Area lies in tehsil Behat.

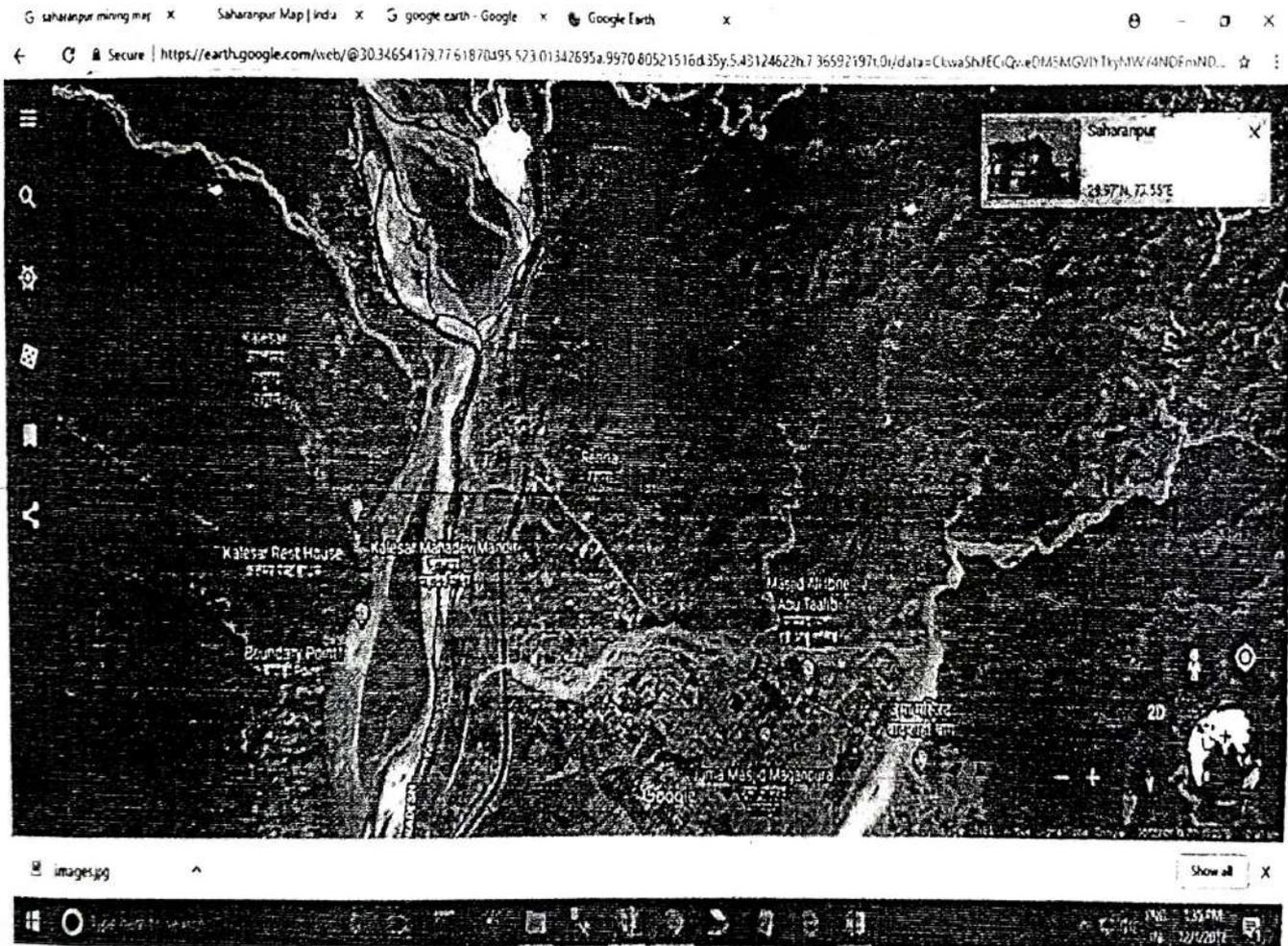
Details of River bed mineral areas available for mineral concession after getting environment clearance.

Sr. No.	Zone	Lot no.	Area in acres	Village	Mineable Mineral Potential (Qubic meter)
01	A	03	19.00	Rahana	1384.62
02	A	04	25.50	Rahana	1858.30
03	A	05	25.50	Rahana	1858.30
04	A	17	56.00	Akbarpur Bans	4080.97
05	A	18	26.00	Chhaja Ehtmal	1897.47
06	A	21	49.00	Allauddin purbas	3570.85
07	A	37	60.00	Nunyari Ehtmal	4372.47
08	A	40	90.60	Aslampur Bartha	6602.43
09	A	06	30.60	Faizabad	2229.96
10	A	20	30.60	Madhti Ehtmal	2229.96
11	A	36	86.00	Rasoolpur urf Rasooly	6267.21
12	A	38	60.00	Nuniyari Ehtmal	4372.47
13	A	39	23.00	Tatohal	1676.11
Total			581.8		
14	B1		130.00	Dariya Baramad	9473.68
15	B2		130.00	Dhikka Kalan	9473.68
Total			260.00		
16	C1	13	31.00	Naurangpur	2259.11
17	C2	24	19.00	Jyantipur Bans Ehtmal	1384.62
18	C2	34	46.32	Kaluwala Pahadipur	3375.55
19	C2	23	23.00	Jyantipur Bans Ehtmal	1676.11
20	C2	22	9.88	Jyantipur Ehtmal	7200.00
21	C2	33	16.00	Kaluwala jahanpur	11660.00
22	C3	10	30.00	Thapul Islamailpur	21862.3

Map showing rivers in which mineral sand, bajari and boulder in mix state is found in district Saharanpur.



Map showing Yamuna river bed mineral area in village Rahena Lot no 3, 4, 5 in district Saharanpur.



Map showing Yamuna river bed area in village Chajja Ehtmal lot no 18, Akbarpur Bans lot no. 17, Allaudeenpur Bans lot no. 21 in district Saharanpur.



-14-

Map showing Yamuna river bed area in village Aslampur Bartha lot no 40, Rasoolpur urf Rasooli lot no. 36 in district Saharanpur.



Map showing Yamuna river bed mineral area in village Nunyari ehtmal lot no.37, 38 & Tatohal lot no 39 in district Saharanpur.

Saharanpur Map | Index

www.maplandia.com/india/uttar-pradesh/saharanpur/saharanpur/

Location Map Map with Street View World Map with Countries



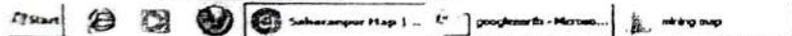
10 people like this. Sign up to see what your friends like.

small | medium | large

START NOW

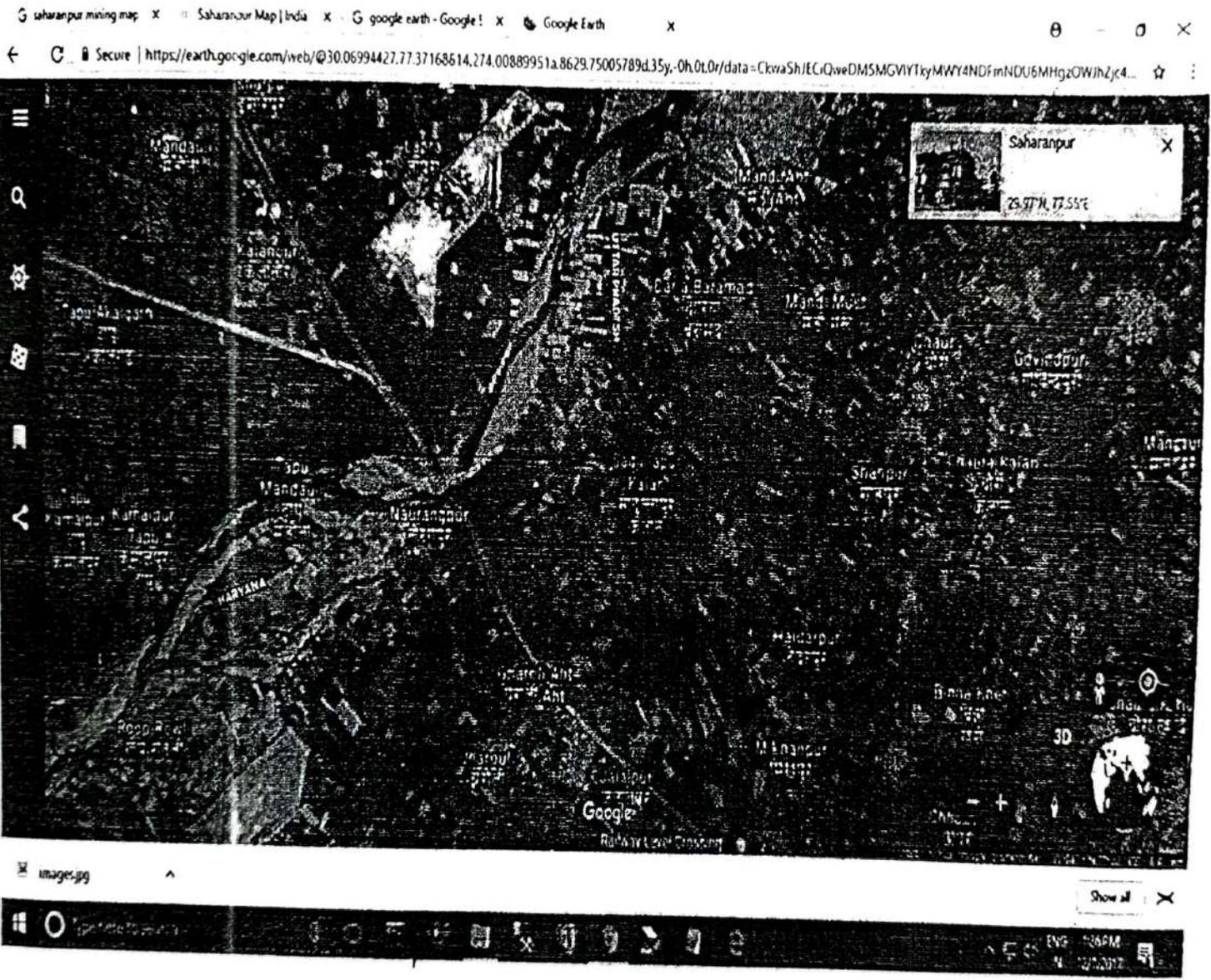
Start Download - View

Convert From Doc to PDF, PDF to Doc



EN | ... | ...

Map showing river bed area B1 Dariya Baramad, B2 Dhikka kalan in river Yamuna in district Saharanpur.

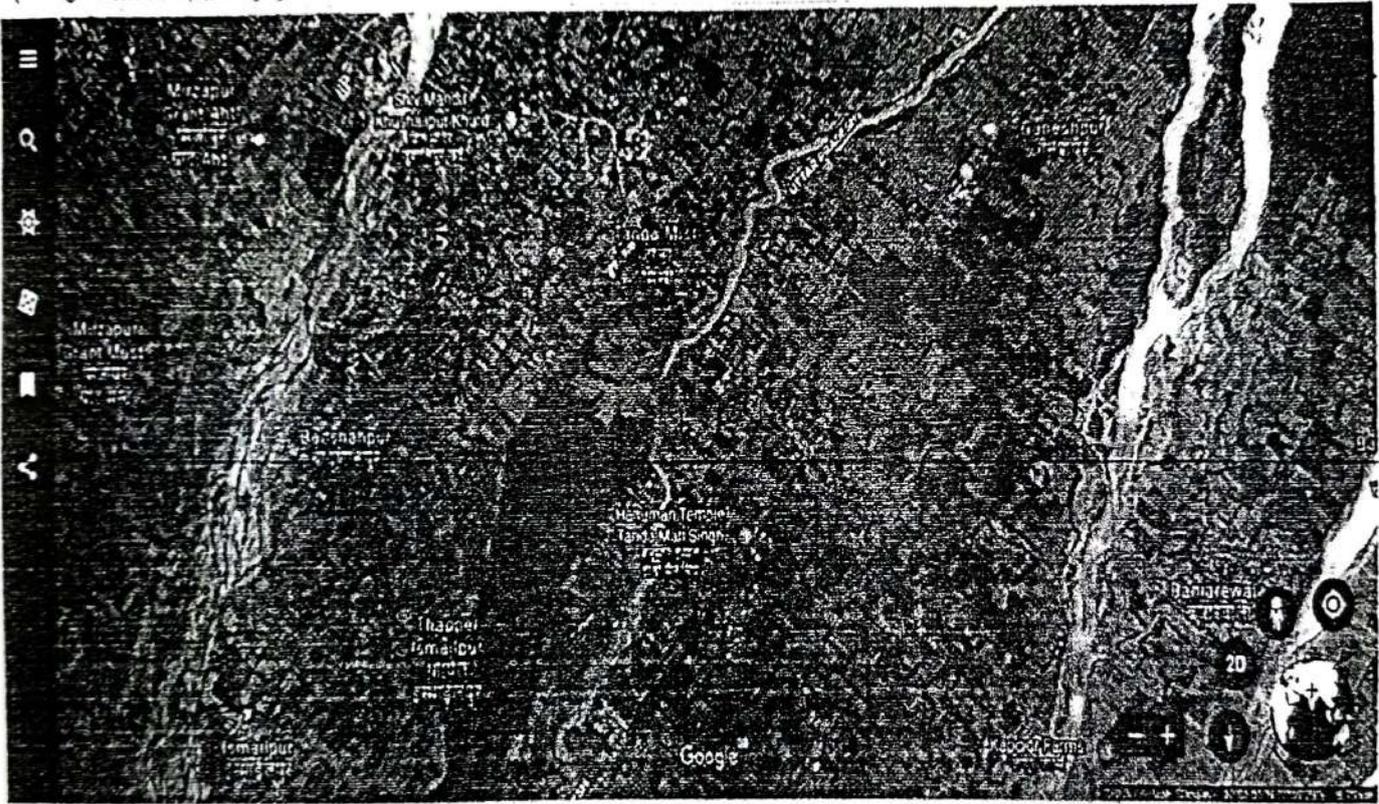


Map showing Khairon wali riverbed mineral area village Sherpurpelo lot no.1 in district Saharanpur.



Map showing kaluwala river bed mineral area in village thapul ismailepur sub zone C2 lot no. 24, 34, 23, 22, 33 and solani river bed mineral area lot no.9, 10, 11, 25, 28, 29, 30, 31 and lalo river bed mineral lot no. 12 in district Saharanpur.

G saharanpur mining map X - Saharanpur Map | India X - G google earth - Google S X / Google Earth X
Secure | <https://earth.google.com/web/@30.1240329,77.84148066,336.1687141a,6507.42586476d,35y,0h,9.58213852L0r>



Images.gs Show all X



23	C3	11	17.30	Thapul Islamailpur	126273
24	C3	25	13.80	Abdullapur	100567
25	C3	28	22.00	Badshahpur	160324
26	C3	30	25.50	Khushhalipur	185830
27	C3	31	46.32	Khushhalipur	337555
28	C3	29	33.00	Badshahpur	240486
29	C3	9	17.00	Thapal Ismailpur	123887
30	C4	1	19.00	Sherpur Pelo	138462
31	C5	7	6.00	Faizabad	43725
32	C5	8	17.00	Faizabad	123887
33	C6	26	23.00	Mayapur Rooppur	167611
34	C6	27	36.72	Mayapur, Rooppur	267595
35	C7	15	15.44	Fatehpur Pelo	112518
36	C7	16	12.35	Fatehpur Pelo	90000
37	C8	12	16.92	Ganeshpur	123304
Total			496.25		

Conditions to be imposed

- (a) As per provision of rule 41 (e) of UP minor mineral concession Rules, 1963, No mining shall be carried on at or to any point within a distance of 50 meter from any Railway line except with the previous written permission of the Railway administration concern or from any Reservoir, Canal or other Public work such as public road and building or inhabited site except within the previous written permission of the District Officer or any other officer authorized by the State Government in this behalf and otherwise than in accordance with such instructions and conditions either general or special, which may be attached such permission. The said distance of 50 meter shall be measure in case of Railway, Reservoir, Canal, or road horizontally from the outer toe of the bank or the outer edge of the cutting has the case may be and in case of a building horizontally from plinth thereof provided that the distance in the case of village road shall be 10 meters from the outer edge of the cutting.
- (b) As per the provision of Rule 41 (g) of UP minor mineral concession Rules, 1963, the lessee is bound to keep vigilance for not polluting the environment of the lease hold area and the nearby area in connection with mining operation and also maintain ecological balance of the area. If at any time it is found that the mining operation are leading to environment pollution or imbalance of ecology, then after giving an opportunity of being heard the lease may be prematurely terminated.
- (c) As per the G.O. No.- 8168A/9-1-90-(4)/General/89 dated 02.02.1990 of Nagar Vikas Vibhag, U.P. Government mining of sand and earth is prohibited within one kilometer from major bridges on both sides.
- (d) As per G.O. No.- 4805/18-12-92-121/91 dated 31.10.1992 of Udyog Anubhag-12 areas restricted for mining from any Dam or major bridge should be decided after discussion with PWD and Irrigation department concerned.
- (e) As per the provisions of Rule 34(4) of UP minor mineral concession Rules, 1963, mining operation shall in respect of sand or morrum or bajari or boulder or

any of these in mixed state exclusively found in river bed be undertaken in accordance with the mining plan, detailing yearly development schemes, aspect of reclamation and rehabilitation of mined out area including progressive mine closure scheme duly approved by the Director. Provided that the lessee shall start the mining operation after obtaining environmental clearance if required under the provisions of the Environment Impact Assessment Notification, dated September 14, 2006 issued by the Ministry of Environment & Forests, Government of India as amended from time to time. As per the Provisions of Rule 34(6) financial assurance has to be deposited by the lessee at the time of the execution of the lease at the rate of Rs. 25000 per acre that to minimum Rs. 2.00 lakh to ensure the undertaking for reclamation and rehabilitation of the area.

- (f) **As per the provisions of Rule 34(5) of UP minor mineral concession Rules, 1963** The mining lease deed will be executed only after approval of mining plan by the Director after which the lessee shall commence mining operations within six months from the date of execution of the lease deed and shall thereafter conduct such operations without deliberate intermission in a proper, skilful and workman like manner.
- (g) **As per the provisions of Rule 17 (1) of UP minor mineral concession Rules, 1963** when a mining lease is granted, arrangement shall be made by the Director for survey and demarcation of the area granted under the lease and then as per Rule 35 the lessee shall after the survey and demarcation of the area granted under the lease and before executing the lease deed, at his own expense, erect and at all times maintain and keeping good repair boundary marks and pillars necessary to indicate the demarcation shown in the lease deed.
- (h) **As per the provisions of Rule 41(h) of UP minor mineral concession Rules, 1963** the lessee shall not do any mining operation beyond the depth of 3 meters of water level which ever is less in the river bed and no mining shall be carried out in the safety zone so worked out by the District Officer.
- (i) Sand/ Gravel will be collected in slices of 1.0 m thickness up to a maximum depth of 3.0 m or river bed water level.

- (j) Mining at the concave side of the river channel shall be avoided to prevent bank erosion; rather a thick barrier will be left this side.
- (k) Mining will be restricted minimum 7.5 m away (inward) from river bank but up to 10% of width of river whichever is higher as a safety barrier to minimize effect of river bank erosion and to avoid consequent channel migration. Plantation will be done on side of bank along side of lot area to prevent soil erosion and to get as a noise/dust arresters.
- (l) Mining shall be done from stream to river bank.
- (m) Between every mining lots or lease area a barrier of 100 meter should be left to check the river flow.

Turtle nesting areas

~~There are no turtle nesting areas in the stretches of the river of District Saharanpur.~~

Closed Season for mining

The India Meterological Department Nagpur, vide letter no. Nagpur RMC/CS-312 dated 18 Jan 2016 has provided the period of rainy season State wise. AS per the India Meterological Department report the period of rainy season viz normal dates of on set and withdrawal of southwest monsoon over India as State wise for the State of U.P. it is from 15th June to 1st October (3.5 month) and for the State of Haryana it is from 1st July to 15th September (2.5 month), Whereas for Saharanpur (Uttar Pradesh) and Yamuna Nagar (Haryana) it should be same.

PROVISION FOR MINERAL CONCESSION

Section 15 of MMDR Act 1957 empowers the respective State Government to make rules for regulating the grant of quarry leases, mining leases or other mineral concession in respect of minor minerals. In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 15 of the Mines and Minerals (Regulation & Development) Act, 1957, the Government of Uttar Pradesh has made the Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules 1963, there are 3-ways of mineral concession for river bed minor minerals such as Sand, Bajari, Boulder.

1. Mining lease under Chapter-II.
2. Auction Lease under Chapter-IV.
3. Short term mining permit under Chapter VI.

As per the provision of Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules, 1963, It is purview of the State Govt. to adopt mining lease or auction lease at one time and availability of the area is advertised under rule 72 accordingly. Period of lease of river bed mineral such as sand, bajari, boulder was previously 3 years which has been amended and made to 5 years by 38th amendment dated 14.07.2015 in Uttar Pradesh Minor Mineral Concession Rules, 1963, in view of the judgment and order of Supreme Court dated 27.02.2012 in the matter of Deepak Kumar v/s State of Haryana.

4.1 Mining Lease:

In Mining lease lessee pays annual dead rent/ lease amount or royalty whichever is higher. Here lease amount of a lease area is decided on the basis of highest income received during last 3 years.

4.2 Auction Lease:

In auction lease, lessee pays a bid amount on annual basis and free to excavate any quantity of mineral within the limit of quantity specified in Environmental Clearance and on dead rent/lease amount or royalty is paid.

4.3 Short-term Mining Permit:

A short-term mining permit is granted for maximum six months for a fixed quantity of minerals for which royalty gets deposited in advance.

Present Policy:-

State of U.P. has now come up with a new mining policy 2017. There are objects of the mining policy are summarized here in below:-

- (1) Sustainable socio-economic development.
- (2) Mineral conservation.
- (3) Maintaining balance of environment and ecology.
- (4) Technological interventions to prevent illegal mining and transportation.
- (5) Provisions of strong punishment against the persons involved in illegal mining and transportation.
- (6) Providing employment in the sector of employment and encouraging healthy competition in the mining sector.
- (7) Scientific development of minerals including utilization, marketing and human resource development.
- (8) Encourage private partnership and development of mining industry.
- (9) To explore the new minerals by using modern exploration techniques for the development of minerals.

- (10) Grating of concessions of minerals in a transparent manner through a transparent policy.
- (11) Simplifying the mining administration and making it more transparent/robust so as to make it corruption free.
- (12) To start developmental and beneficial schemes for person and areas affected by mining activities.

In pursuant to promulgation of the new mining policy 2017 State of U.P. amended its minor mineral concession rule 1963 vide notification no. 1956/LXXXVI-2017-56 (shamanaya) dated August 14, 2017.

Details of existing mining leases in river bed in district Saharanpur

At present not a single lease is in river bed area in district Saharanpur.

कार्यालय, जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, सहारनपुर

पत्रांक 1964 / डी0एस0आर0 / सहारनपुर(खनन) / 2018

दिनांक 26-10-2018

शुद्धिपत्र

संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) सहारनपुर

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सहारनपुर जो पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण सहारनपुर द्वारा तैयार किया गया है, में गाटा संख्या सम्बन्धी त्रुटि को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

क्रमांक	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल
1	सदर	दरिया बरामद	1/1	52.63 हे०
2	नकुड	ढिक्काकला	839,841 से 856, 858, 859,860,861,863,864,865, 866,867,871,872,888,889, 406,407	52.63 हे०
3	बेहट	नूनियारी अहतमाल	1/1/1 लाट नं०-38	24.29 हे०
4	बेहट	रहना	03 लाट नं०-3	8.05 हे०
5	बेहट	कालूवाला पहाड़ीपुर	92, 93/1, 94, 116/1, 117/1,118/1,119/1, 120/1,192/1 लाट नं०-34	18.75 हे०

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) सहारनपुर में उक्तानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

(आलोक कुमार पाण्डेय)

जिलाधिकारी

सहारनपुर

o/c

कार्यालय जिलाधिकारी, सहारनपुर।
(खनन अनुभाग)

संख्या : 551/खनन/2019-20

दिनांक 07 सितम्बर, 2019

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
सहारनपुर।

भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 में दिए गए निर्देशानुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति दिनांक 02.12.2017 को जिले के वेबसाइट पर अपलोड किया गया था। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात प्राधिकरण की बैठक दिनांक 04.09.2019 में लिए गए निर्णय के अनुसार 5 नये क्षेत्रों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 04.09.2019 को लिए गए निर्णय का कार्यवृत्त जिले की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें जिससे 21 दिनों में प्राप्त होने वाली टिप्पणियों पर विचार करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)
सहारनपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नाजिर सदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि संलग्न कार्यवृत्त को सर्वसाधारण से टिप्पणी एवं सूझाव प्राप्त करने हेतु कलेक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

अपरजिलाधिकारी (वि०/रा०)
सहारनपुर।

E-Tender-cum-E-Auction of Sand/Morrum/Bajri/Insitu Rocks/Stone Chips in Uttar Pradesh

Report of Saharanpur District (Vigvapti Ref 1959 dtd 1.11.2019)

Block Details	Notified Royalty Rate	Highest IPO received in E-Tender	Highest Bid Received in E-Auction	Overall Highest Bid	Name & Address of Overall Highest Bidder
Block 1	110	121	257	257	ADESH PANDEY/131940 Address: man sarovar garden near green park harungla bareilly, BAREILLY 243001 Contact Person: ADESH PANDEY Telephone No: 9719466666 Email Id: adesh.rudraksh@gmail.com
Block 2	110	333	401	401	RAJESH KUMAR/133669 Address: VILLAGE GARHI BIRBAL INDRI, KARNAL 132054 Contact Person: RAJESH KUMAR Telephone No: 7645077777 Email Id: rajeshkumar2407@yahoo.com
Block 3	110	152	215	215	SHAKUMBAR MINES/100426 Address: H-12 NUMISH CAMP SAHARANPUR, SAHARANPUR 247001 Contact Person: VINOD DHAWAN Telephone No: 9259282013 Email Id: shakumbarmines.sre@gmail.com
Block 4	110	216	399	399	SANJAY BHATIA/133499 Address: 1 472 MAIDA MILL PHATAK RAM CHANDRA PURI LAXMI NAGAR, SAHARANPUR 247001 Contact Person: SANJAY BHATIA Telephone No: 9837040676 Email Id: sanjaymine01@gmail.com
Block 5	110	127	138	138	STAR MINES/130973 Address: C3 HAKIKAT NAGAR NEAR OLD SALES TAX OFFICE, SAHARANPUR 247001 Contact Person: BHANU KARNWAL Telephone No: 9634700492 Email Id: starminessaharanpur@gmail.com
Block 6	110	195	200	200	SATYENDER/133627 Address: VPO KHAIRA NAJAFGARH, NEW DELHI 110043 Contact Person: SATYENDER Telephone No: 8851544682 Email Id: satyender1811@yahoo.in

19/11/19

Note: Prior to issuance of Letter of Intent (LOI) to the highest bidder:-

1. District may cross check above report with MSTC System Generated E-mail sent to the highest bidders.
2. Registration Documents and Solvency/BG of Bidders are required to be verified by district prior to issuance of LOI.
3. District may cross check above report with the Bid Sheet Copy of above Events which may be downloaded from district Tender Committee Member login on MSTC E-Portal. Discrepancy, if any, may please be reported to MSTC at upmines@mstcindia.co.in (0522-4244702)



(शालु ढं, सहायकी
मनेज)

Page 2/2

Note: Prior to issuance of Letter of Intent (LOI) to the highest bidder:-

1. District may cross check above report with MSTC System Generated E-mail sent to the highest bidders.
2. Registration Documents and Solvency/BG of Bidders are required to be verified by district prior to issuance of LOI.
3. District may cross check above report with the Bid Sheet Copy of above Events which may be downloaded from district Tender Committee Member login on MSTC E-Portal. Discrepancy, if any, may please be reported to MSTC at upmines@mstcindia.co.in (0522-4244702)



(शुभम ए. शर्मा)
मान्य

Page 2/2

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर।
पत्रांक 2) / 14-1 सहारनपुर दिनांक 02 / 7) 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सहारनपुर।

विषय:- जनपद सहारनपुर में नये खंनन पट्टा क्षेत्रों के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध करावै जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 2662/खनन क्षेत्र/ई-टेण्डर/2018-19 दिनांक 15.02.2019

महोदय,

उक्त सदरभित पत्र द्वारा विषयांकित कम में अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, को प्रकरण में जांच कर अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु आख्या/संस्तुति प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार अपनी संस्तुति/आख्या प्रेषित की गयी है :-

तालिका-1

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	रेज	क्षेत्रीय वन अधिकारी की आख्या	उप प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या/संस्तुति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बहेट	शेरपुर पैलो	378/2 व 379/2	07.00	बडकला	क्षेत्रीय वन अधिकारी बडकला के पत्रांक 139/14-दिनांक 26.8.2019 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल की आरक्षित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 0.55 कि०मी० एवं कलेसर नेशनल पार्क के ईको सेन्सिटिव जोन से दूरी 17.40 कि०मी० है। प्रकरण में अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।	अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।
2	बहेट	मायापुर रूपपुर	14/1	3.10	बडकला	प्रस्तावित स्थल की आरक्षित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 1.20 कि०मी० एवं कलेसर नेशनल पार्क के ईको सेन्सिटिव जोन से दूरी 15.70 कि०मी० है। प्रकरण में अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।	अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।
3	बहेट	रहना	179/2	3.75	बडकला	प्रस्तावित स्थल की आरक्षित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 2.80 कि०मी० एवं कलेसर नेशनल पार्क के ईको सेन्सिटिव जोन से दूरी 7.80 कि०मी० है। प्रकरण में अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।	अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।
4	बहेट	हैदरपुर हिन्दूवाला	8/1, 19, 22	4.20	शाकुमरी	क्षेत्रीय वन अधिकारी शाकुमरी के पत्रांक मेमो/14 1 दिनांक 20.6.2019 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित स्थल की आरक्षित वन क्षेत्र से हवाई दूरी 1.45 कि०मी० एवं राजार्जी टाईगर रिजर्व से दूरी 22.35 कि०मी० है। प्रकरण में अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।	अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की गयी है।

अतः उक्तानुसार तालिका-1 में वर्णित ग्राम शेरपुर पैलो के गाटा संख्या- 378/2 व 379/2, क्षेत्रफल-7.00 हे०, ग्राम मायापुर रूपपुर के गाटा संख्या 14/1 क्षेत्रफल-3.10 हे०, ग्राम रहना के गाटा संख्या- 179/2, क्षेत्रफल-3.75 हे०, ग्राम हैदरपुर हिन्दूवाला के गाटा संख्या 8/1, 19, 22 क्षेत्रफल 4.20 हे० में खनन कार्य हेतु सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारियों एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर खनन अनापत्ति व्यक्त की जाती है।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित ग्राम फौजाबाद, के गाटा संख्या-3 व 21/2 प्रथम खण्ड क्षेत्र 5.00 हे० एवं गाटा संख्या 14, द्वितीय खण्ड क्षेत्र 6.00 हे० के सम्बन्ध में क्षेत्रीय वन अधिकारी बड़कला द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित क्षेत्र वर्तमान में खनन नदी के तेज बहाव में है, गहरे पानी/तेज बहाव के कारण क्षेत्र के जी०पी०एस० लिये जाया सम्भव नहीं है। इस प्रकार उक्त क्षेत्र की आरक्षित वन क्षेत्र एवं कलेसर नेशनल पार्क से दूरी का सही आंकलन वर्तमान में सम्भव न होने के कारण उक्त क्षेत्र (फौजाबाद, प्रथम खण्ड एवं द्वितीय खण्ड) में खनन कार्य हेतु अनापत्ति दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

विषयांकित कम निम्नांकित तालिका-2 में अंकित क्षेत्रों की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी मोहण्ड द्वारा अपने पत्रांक मेमो/14 दिनांक 25.6.2019 द्वारा प्रेषित की गयी है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

तालिका-2

क्र० सं०	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे०)	रेज	क्षेत्रीय वन अधिकारी की आख्या	उप वनाधिकारी की आख्या/ संस्तुति	प्रभागीय की
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बेहट	धापुल इस्माइल पुर	333क, 332, 2218ग.	4.251	मोहण्ड	प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वन से दूरी 875 मी० एवं राजाजी टाईगर रिजर्व से दूरी 3.56 कि०मी० है, इस प्रकार क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की 10 कि०मी० दूरी क्षेत्र/ईको सेन्सिटिव क्षेत्र में आता है जिसके कारण प्रकरण में खनन हेतु असहमति दी गयी है।	अनापत्ति किये जाने हेतु असहमति दी गयी है।	निर्मित हेतु गयी है।
2	बेहट	फतेहपुर पेलियो	428/1 (प्रथम खण्ड)	10.00	मोहण्ड	प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वन से दूरी 1.17 मी० एवं राजाजी टाईगर रिजर्व से दूरी 4.94 कि०मी० है, इस प्रकार क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की 10 कि०मी० दूरी क्षेत्र/ईको सेन्सिटिव क्षेत्र में आता है जिसके कारण प्रकरण में खनन हेतु असहमति दी गयी है।	अनापत्ति किये जाने हेतु असहमति दी गयी है।	निर्मित हेतु गयी है।
3	बेहट	फतेहपुर पेलियो	407/1, (द्वितीय खण्ड)	10.00	मोहण्ड	प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वन से दूरी 1.22 मी० एवं राजाजी टाईगर रिजर्व से दूरी 5.18 कि०मी० है, इस प्रकार क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की 10 कि०मी० दूरी क्षेत्र/ईको सेन्सिटिव क्षेत्र में आता है जिसके कारण प्रकरण में खनन हेतु असहमति दी गयी है।	अनापत्ति किये जाने हेतु असहमति दी गयी है।	निर्मित हेतु गयी है।
4	बेहट	जयन्ती पुर अहतमाल	221	10.00	मोहण्ड	प्रस्तावित क्षेत्र की आरक्षित वन से दूरी 6.50 मी० एवं राजाजी टाईगर रिजर्व से दूरी 9.41 कि०मी० है, इस प्रकार क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व की 10 कि०मी० दूरी क्षेत्र/ईको सेन्सिटिव क्षेत्र में आता है जिसके कारण प्रकरण में खनन हेतु असहमति दी गयी है।	अनापत्ति किये जाने हेतु असहमति दी गयी है।	निर्मित हेतु गयी है।

अतः उक्त तालिका संख्या-2 में वर्णित क्षेत्र राजाजी टाईगर रिजर्व के 10 कि०मी० रेडियस/ईको सेन्सिटिव जोन में होने के कारण तालिका संख्या-2 में अंकित कम संख्या 1 से 04 तक के क्षेत्रों में खनन कार्य हेतु अनापत्ति व्यक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

भववीर
(आर०बी०बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग,
सहारनपुर

पत्रांक /14-1दिनांकित।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एव विषयांकित कम में उनके द्वारा की गयी संस्तुति के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु

- 1 उप प्रभागीय वनाधिकारी शिवालिक वन प्रभाग सहारनपुर।
- 2 समस्त क्षेत्रीय वन अधिकारी शिवालिक वन प्रभाग,

(आर०बी०बालाचन्द्रन)
प्रभागीय वनाधिकारी
शिवालिक वन प्रभाग
सहारनपुर।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

S.O. 1485(E).—Whereas, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 2540(E), dated 17th September, 2015 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 17th September, 2015;

And whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

And whereas, the Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary of about 100.88 square kilo meter are located on the junction of the four states, viz., Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Uttrakhand and Haryana, it falls in Shiwalik foot hills, and shares boundaries with two protected areas of two different states, namely, the Simbalbarha Wildlife sanctuary of Himachal Pradesh towards the North and the Rajaji National Park of Uttrakhand towards the East and Kalesar Wildlife Sanctuary is just towards the East-West of Kalesar National Park and as such there does not exist any physical barrier between the two and the entire area is very rich in plant and animal species and have historical, economic and medicinal significance and the Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary are rich in reptilian fauna which includes large monitor lizard, India rock python, King cobra, common krait, Red snake, Russel viper, Pit viper etc.;

And whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to the extent of upto 1900 meters from the boundary of the protected area of Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary within the State of Haryana as the Kalesar Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**—(1) The Eco-sensitive Zone varies from zero to 1900 meters from the boundary of Kalesar National Park and Kalesar Wildlife Sanctuary within the State of Haryana and the area of Eco-sensitive zone is 38.92 square kilo meter approximately. The co-ordinates of Kalesar National Park and Wildlife Sanctuary are given at Annexure-I.

(2) The Eco-sensitive Zone is bounded by 30°18'49.861"N latitude and 77°35'7.269"E longitude towards East-South (point No.14 of Annexure I map); 30°24'35.016"N latitude and 77°24'37.293"E longitude towards west (point No.1 of Annexure IA map); 30°18'2.561"N latitude and 77°32'26.990"E longitude towards South (point No. 12 of Annexure I map) and Simbalbara National Park of Himachal Pradesh is falling on the Northern side and on Eastern side of Yamuna River.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitudes and longitudes is appended as Annexure IA.

(4) The coordinates of Eco-sensitive Zone with its latitudes and longitudes are appended as Annexure II.

(5) The villages whose area or parts thereof falling within the Eco-sensitive Zone are, Ibrahimpur, Taharpur Kalan, Taharpur Khurd, Fakir Majra, Fatehgarh, Kot Mushtarka, Bachchon, Shahabuddinpur Kalan, Shahabuddinpur Khurd, Yarali, Sipanwala, Jatanwala, Darpur, Baniwala, Kansli, Chikan, Khilanwala, Bagpat, Khizri, Ambwali, Tibriyon, Nagalpatti Milak, Baumbewala, Chandpur, Rayanwala, Jhandu Oad, Faizpur, Kalesar, Garhi, Banjarwas, Mamduwas.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people in accordance with this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in accordance with this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment;
- (ii) Forest;
- (iii) Urban Development;
- (iv) Tourism;
- (v) Municipal;
- (vi) Revenue;
- (vii) Agriculture; and
- (viii) Haryana State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, as on the date of publication of this notification in the Official Gazette, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.—The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**—Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 27, 35 and 40 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

- (i) small scale industries not causing pollution;
- (ii) rainwater harvesting; and
- (iii) cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the

provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**—The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**—(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Haryana in consultation with the Department of Revenue and Forests, Government of Haryana.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**—All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**—Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines or, as the case may be regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**—The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines or, as the case may be regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**—The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974(6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.**—Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000, published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 908(E), dated the 25th September, 2000, as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**—The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998, published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998, as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.**—(a) The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government.

(b) The Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.—All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
A. Prohibited Activities:		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 202 of 1995 and dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No. 435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new and expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
6.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सहारनपुर।

पत्रांक 4299/141 दिनांक, सहारनपुर 17-6-2019

सेवा में

जिलाधिकारी
सहारनपुर।
(खनन अनुभाग)

विषय- जनपद सहारनपुर में नये खनन पट्टा क्षेत्रों के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने विषयक।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक 2662/खनन क्षेत्र/ई-टेण्डर/2018-19 दिनांक 15.02.2019
महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में क्षेत्रीय वनाधिकारी, बेहट द्वारा जाँच कराई गई। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि बेहट रेंज के अन्तर्गत ग्राम बरथा कोरसी के गाटा संख्या-01 क्षेत्रफल 36.00 हेक्टर की जाँच आरक्षित वन क्षेत्र से एवं हरियाणा राज्य के कलेशर राष्ट्रीय उद्यान से दूरी के संबंध में की गई। जाँच के दौरान शिवालिक वन प्रभाग के आरक्षित वन क्षेत्र मगनपुरा मुनारा संख्या -908 की जी०पी०एस० N30°20'04.4" E077°37'04.0" है तथा खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम बरथा कोरसी गाटा संख्या-1 की जी०पी०एस० रिडिंग N30°14'37.1" E077°31'40.8" है। जी०पी०एस० रिडिंग के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र से खनन पट्टा क्षेत्र की दूरी 13.30 किमी है। इसी प्रकार कलेशर राष्ट्रीय उद्यान की जी०पी०एस० रिडिंग N30°18'44.0" E077°34'26.9" है। जी०पी०एस० रिडिंग के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान से खनन पट्टा की दूरी 8.83 किमी है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में यमुना नदी का पानी बह रहा है। जाँच के दौरान श्री लेखपाल सिंह वन दरोगा, श्री शिबू कुमार, सर्वेयर खनन विभाग, मौ० आशिफ खान, लेखपाल राजस्व विभाग उपस्थित रहे।

भवदीय

(विजय सिंह)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
सहारनपुर

संख्या- 3213 / खनन/2019-20

दिनांक- 30/12/2019

खनन पट्टा हेतु सहमति पत्र
(Letter of Intent)

मेसर्स स्टार माइन्स
पता सी-3, हकीकत नगर
निकट ओल्ड सेल्स टेक्स आफिस,
सहारनपुर
पार्टनर श्री दीपक चौधरी

शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57(स)/2017टी0सी0-1 लखनऊ दिनांक 09.10.2019 के द्वारा प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उप खनिज बालू/मौरम/बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से पांच वर्ष की अवधि हेतु परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु जनपद सहारनपुर के ग्राम बरथा कोरसी गाटा संख्या 1 क्षेत्रफल-36.00 हे० में 756000 घ०मी० बालू/बजरी/बोल्डर का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु विज्ञप्ति संख्या 1959/खनिज/2019-20 दिनांक 01.11.2019 एम०एस०टी०सी० के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर अपलोड करते हुए ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रित की गयी थी। ई-निविदा सह ई-नीलामी की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अधिकृत नोडल एजेंसी एम०एस०टी०सी० द्वारा निर्धारित समय अवधि में की गयी। एम०एस०टी०सी० के ई-मेल पत्र दिनांक 16.12.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि:-

तहसील	नदी का नाम	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल(हे०में)	उपखनिज की मात्रा (घ०मी०)
सदर	यमुना	बरथा कोरसी	1	36 हे०	7,56,000

उपरोक्त में आपके द्वारा ई-नीलामी में अधिकतम ऑफर रू० 138/- प्रति घनमीटर दी गयी है। आपके द्वारा ग्राम बरथा कोरसी हेतु बालू/बजरी/बोल्डर की मात्रा 7,56,000 घनमीटर की कुल धनराशि रू० 10,43,28,000/- प्रथम वर्ष हेतु दी गयी है।

- 1- निर्बन्धन एवं शर्तों का पालन करने के लिए प्रतिभूति के प्रथम वर्ष के लिए बोली की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति की धनराशि रू० 2,60,82,000/- तथा 20 प्रतिशत धनराशि रू० 2,08,65,600/- प्रथम वर्ष की पहली किस्त के रूप में दो कार्य दिवसों के अन्दर खनन कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराना होगा। आफरदाता द्वारा पूर्व में जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी रू० 2,07,90,000/- को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू० 2,61,57,600/- जमा करना होगा। यदि लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी करने के दो कार्य दिवसों में अवशेष धनराशि जमा करने में आप असफल होते हो तो आप द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा आफरदाता द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 2 उपखनिज का पट्टा पांच वर्ष हेतु जारी किया जायेगा। प्रथम वर्ष की धनराशि रू० 10,43,28,000/- तथा अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की ई-नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए देय होगी।
- 3- प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि 30प्र० उप खनिज परिहार नियमावली 1963 (यथा संशोधित) में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी। देय किस्त की धनराशि जमा न करने की दशा में नियम 59 के अनुसार देय धनराशि पर नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- 4- लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, 30प्र० लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन



योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अथवा नियम 59(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत 10,000 प्रति दिन की शास्ति आरेपित किया जाएगा।

- 5- पट्टाधारक नियम 17 के प्राविधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेंगे।
- 6- पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
- 7- नियम 34(4) के अन्तर्गत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा। नियम 34(4) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट नियम 59(7) के अन्तर्गत जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जा सकता है।
- 8- नियम 34(5) के अन्तर्गत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। नियम 34(5) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त एवं प्रतिभूमि धनराशि समपूहृत करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त किया जायेगा।
- 9- पट्टाधारक द्वारा नियम 35 के प्राविधानों के अन्तर्गत माइन्स क्लोजर प्लान तथा भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपटित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करेंगे।
- 10- पट्टाधारक द्वारा नियम 34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार एवं पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करायेंगे।
- 11- पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर का दो प्रतिशत टी0सी0एस0 (वर्तमानदर) एवं 10 प्रतिशत धनराशि जिला सहारनपुर खनिज फाउण्डेशन न्यास में नियमानुसार जमा करायेंगे।
- 12- पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व मे पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने को आवश्यक होगा।
- 13- पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जानबुझकर कोई स्थागन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण कुशल कारिगर की भांति करेगा।
- 14- पट्टाधारक नियम 35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व किसी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार आई0वी0आर0 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने सहित चैकपोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चैकपोस्ट/गेट पर आरएफआईडी स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सीसीटीवी कैमरे और आरएफआईडी स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम 66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर रिकार्ड को उपलब्ध करायेगा।
- 15- पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा, प्रत्येक वाहन को निर्गत ई एम0एम0-11 जनित बार कोड को चैकगेट पर पढने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आरएफआईडी स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली 1963 के नियम 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
- 16- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन मे पट्टा धारक द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त साफ्टवेयर में इन्टीग्रेट किया जायेगा। इन्टीग्रेटस में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-

- (1) The Weight bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
(2) The Weight bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastucture in cloud.

- 17- पट्टाधारक तीन मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें नहीं करेगा।
18- जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जाएगा।
19- नदी की जल धारा में संक्शन लिफ्टर आदि मशीन द्वारा खनन कार्य नहीं किया जाएगा।
20- स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिहवन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा।
21- यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारियों अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
22- उ०प्र० उपखनिज परिहार नियमावली 1963 के नियम 67 के अधीन भूमि को स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं पट्टेधारक के मध्य तय होगा।
23- पट्टा धारक द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही अनुमति प्राप्त कर खनन प्रारम्भ किया जाएगा।
24- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारक को मान्य होगा।
25- माननीय उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।


जिलाधिकारी
सहारनपुर
६

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार

- प्रतिलिपि:- 1-प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म शासन लखनऊ, को सादर सूचनार्थ।
2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ को सूचनार्थ।




जिलाधिकारी
सहारनपुर
९

DISTRICT SURVEY REPORT FOR SUSTAINABLE SAND MINING DISTT. YAMUNA NAGAR

The Boulder, Gravel and Sand are one of the most important construction materials. These minerals are found deposited in river bed as well as adjoining areas. These aggregates of raw materials are used in the highest volume on earth after water. Therefore, it is the need of hour that mining of these aggregates should be carried out in a scientific and environment friendly manner. In an endeavour to achieve the same, District Survey Report, apropos "the Sustainable Sand Mining Guidelines" is being prepared to identify the areas of aggradations or deposition where mining can be allowed; and identification of areas of erosion and proximity to infrastructural structural and installations where mining should be prohibited and calculation of annual rate of replenishment and allowing time for replenishment after mining in that area.

1. Introduction:-

Minor Mineral Deposits:

- 1.1 Yamunanagar district of Haryana is located in north-eastern part of Haryana State and lies between 29° 55' to 30° 31' North latitudes and 77° 00' to 77° 35' East longitudes. The total area is 1756 square kilometers, in which there are 655 villages, 10 towns, 4 tehsils and 2 sub-tehsils. Large part of the district of Yamunanagar is situated in the Shiwalik foothills. The area of Yamuna Nagar district is bounded by the state of Himachal Pradesh in the north, by the state of Uttar Pradesh in the east, in west by Ambala district and south by Karnal and Kurukshetra Districts.
- 1.2 The district has a sub-tropical continental monsoon climate where we find seasonal rhythm, hot summer, cool winter, unreliable rainfall and immense variation in temperature. In winters, frost sometimes occurs during December and January. The district also gets occasional winter rains from cyclones. The rain fall is mostly restricted to rainy season. The district has Shivalik hills and foot hill rolling plain in the north and north- east, and flood - plain along the Yamuna River in the east and south- east. The

important rivers/ streams of the district are Yamuna, Sarasvati, Chautang, Rakshi, Somb, Boll, Fandi Rao etc.

- 1.3 Boulder, Gravel and Sand (Minor Minerals) finding use as construction material are found in the river bed areas and flood plain areas. The size and the concentration of material gradually reduce towards down stream as the heavy material of larger size settles with reduction in flow of water stream. The mineral deposits are found in villages of the districts located along the river or their flood plains and abandoned water courses/drains as well as along with foothills of the hilly terrains.
- 1.4 All rivers/drainage systems in the district Yamunanagar other than river Yamuna are seasonal rivers. Even the water of river Yamuna at Hathanikund Barrage is diverted partly towards Uttar Pradesh and Haryana through different Canal Systems for Irrigation purposes. In the main river bed area the water is released from Hathni Kund Barrage during rainy seasons. The water released in the river during rainy season brings huge quantity of Boulder, Gravel and Sand which gets deposits in the river bed area. The flood plains also have huge deposits of Boulder, Gravel and Sand up to a depth of 10-12 meter.
- 1.5 The river Yamuna acts as natural boundary between the State of Haryana and Uttar Pradesh. Part area of river Yamuna in the State of Uttar Pradesh and part area falls in the State of Haryana. Though, in general western part falls in Haryana and eastern part in Uttar Pradesh. But at certain places, the entire area of river (both side of river bank) falls in either of state. In other words there are areas of river where entire riverbed area falls within the jurisdiction of Haryana or Uttar Pradesh.
- 1.6 The Boulder, Gravel and Sand deposits are not found only in river Yamuna but also in the other rivers/tributaries of river Yamuna or rivulets like Yamuna, Chautang, Rakshi, Somb, Boll, Fandi Rao etc. passing through other parts of district Yamunanagar as well as in adjoining areas outside the river bed.

Minor Mineral Bearing Areas:-

- 1.7 The minor mineral deposits in the district Yamunanagar can be divided mainly in five categories
 - i. Areas in Yamuna riverbed.
 - ii. Areas outside river Yamuna bed.
 - iii. Sand bearing areas in Yamuna riverbed.
 - iv. Areas in river bed of other rivers like Chautang, Rakshi, Somb, Boll, Fandi Rao etc.
 - v. Areas outside/flood plains of other rivers.

2. Overview of Mining Activity in the District

Mode of grant of mineral concession

- 2.1 Before giving details of actual sites / number of sites or mineral concessions it would be appropriate to explain that the Mineral Concession in respect of minor minerals are granted as per the provisions of the State Rules, framed by the State Government in exercise of powers conferred under section 15 of the Mines and Minerals (D&R) Act, 1957.
- 2.2 The State of Haryana at the time of bifurcation opted prevailing Rules namely "Punjab Minor Mineral Concession Rules 1964". These Rules were amended from time to time as per policy of the State Government. The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 27.02.2012 directed all State Governments to revise their State Rules making provisions in accordance with various recommendations contained in the report of the MoEF & CC, GoI, on mining of minor minerals and the Model draft guidelines issued by the Ministry of Mines, GoI.
- 2.3 Accordingly, the State of Haryana framed & notified on 20.06.2012 comprehensively revised Rules namely, the "Haryana Minor Mineral Concession, Stocking, Transportation of Minerals, and Prevention of Illegal Mining Rules, 2012", repealing the prevailing Rules namely "Punjab Minor Mineral Concession Rules 1964".
- 2.4 The mineral concessions in the Haryana are being granted in the form of "Mining Contract" or "Mining Lease" through competitive bidding process. The Mining Contracts are granted for a minimum period of 07 years and

maximum period of 10 years. Whereas the Mining Leases are granted for a minimum period of 10 years and maximum period of 20 years. In district Yamuna Nagar mineral concessions are/were granted in the form of Mining contracts for the period varying between 7 to 10 years. The contracts are being granted through open auction/ e-auction mode. The Mineral concessions are being granted subject to condition that actual mining operation shall be allowed only after environment Clearance is/are obtained from the competent authority as per requirement of EIA Notification dated 14.09.2206 of the MoEF & CC, Gol.

- 2.5 The mineral concession holders are required to prepare a detailed “**Mining Plan**” for their specific project through Registered Qualified Person and get in approved from authorized officer of the State Government. The exhaustive mining plan are prepared interalia giving details of mineral reserves, method of mining, extent of proposed mining and other related details. These are the projects specific details. Based on these details itself the project proponents/ mineral concession holders obtains environmental clearances.

3. Method of Mining and Conditions in which mining in river bed areas is to be allowed

- 3.1 The river bed areas apart from other related condition for mining are allowed to excavate minerals (Boulder, Gravel or Sand) to ensure safety of rivers bed structures and the adjoining areas on the following specific conditions:
- (i) No mining would be permissible in a river-bed up to a distance of five times of the span of a bridge on up-stream side and ten times the span of such bridge on down-stream side, subject to a minimum of 250 meters on the up-stream side and 500 meters on the down-stream side;
 - (ii) There shall be maintained an un-mined block of 50 meters width after every block of 1000 meters over which mining is undertaken or at such distance as may be directed by the Director or any officer authorized by him;
 - (iii) The maximum depth of mining in the river-bed shall not exceed three meters measured from the un-mined bed level at any point in time with proper bench formation;
 - (iv) Mining shall be restricted within the central $3/4^{\text{th}}$ width of the river/ rivulet;

- 3.2 **Note:** The above said conditions have been decided after detailed discussions and recommendations of the PWD (B & R) department and Irrigation department, Haryana.
- 3.3 As the mining in river bed remains restricted in the Central 3/4th part of the river bed, the area left on both side of the river bank not only ensures the safety of banks (bank cutting due to water stream) but also ensures that in the central part of river, water stream flows smoothly during rains and process of river meandering does not occur.
- 3.4 The light weight excavator/JCBs are being deployed to remove mineral from river bed up to maximum depth of 03 meter layer from general level of the bed. The mining in the river bed are undertaken in mechanized manner. At times the RQPs do refers the excavation in river bed mining through excavators as "Semi Mechanized Mining".
- 3.5 The mineral excavated is directly loaded in the vehicles/dumpers and the vehicle owners and drivers take away the mineral directly to the stone crushers or screening plants or consumers. In certain cases mineral concession holders stacks mineral on the river bank in case are not able to sell the material on actual mining itself.

4. Method of Mining in areas outside river bed:

- 4.1 The excavation of minerals (Boulder, gravel, Sand or Sand) found outside river bed areas are also being permitted. The opencast mining of Boulder, gravel & Sand or Sand from areas outside river bed is similar to that of any kind of open cast mining.
- 4.2 As the minerals (Boulder, gravel & Sand or Sand) are found in and adjoining river bed areas also, therefore, to ensure that mining from outside do not affect rivers, no mining is being permitted in an area up to a width of 500 meters from the active edges of embankments in case of river Yamuna, 250 meters in case of Tangri, Markanda and Ghaggar and 100 meters on either side of all other rivers/ rivulets.
- 4.3 The mineral excavation from areas outside river bed is being permitted subject to condition that a safety margin of two meters (**2m**) shall be maintained above the ground water table while undertaking mining and no mining operations shall be permissible below this level unless a specific permission is obtained

from the competent authority in this behalf. Further the depth of excavation of mineral shall not exceed nine meters (9m) at any point of time.

4.4 The method of excavation is such that the mining contractors deploys earth moving machineries and after removing the top layer of original soil, varying between 1 to 1.5 meters, stack the same separately. Thereafter removes the minor mineral deposits. After undertaking the mining i.e. removing of mineral layer up to a maximum depth of 09 meter, the top stacked soil is again spread back into the pit. The mined out area/ land is put to reuse for cultivation after spreading the top soil. The landowners/farmers give their land to the contractors for mining after getting compensation, mutually settled between the landowners and the mining contractor.

5. Method of Mining in river bed areas (semi-mechanized/mechanized or manual)

5.1 The Hon'ble NGT with regards to river bed mining has specifically desired to examine the mode of mining – shall the same be **semi mechanized /mechanized or manual**.

5.2 There is no specific definition of **Semi – Mechanized Mining**. The term Semi – mechanized mining in general is used where method of working in general are undertaken mechanically, however, some operations are also undertaken manually. Therefore, the semi mechanized mining or mechanized mining, is the same method of working. Sometime mechanized mining with light machines are also referred as semi- mechanized mining. The term semi mechanized mining is being used in general parlance where in the very same mining area in part area as per requirement manual mining is also undertaken along with mechanized mining of sand/river bed mining.

5.3 Whereas **Manual** mining operations are undertaken using conventional hand tools only like Spade, Pan, Crowbar etc. and operations are only labour intensive. As per requirement in manual mining lifting of sand and directly loading the sand in tractor trolleys etc. is being carried out through labours itself.

5.4 The **Mechanized** mining operations in respect of sand mining are undertaken with the help of excavator-cum-loaders. In this process sand is lifted/excavated from the river bed through excavator-cum-loaders and directly loaded in

dumpers or other mode of transport. The vehicles carrying the mineral from mines to site of use/ site of construction or sale stocks outside lease hold areas (*an independent business than that of mining*).

5.5 In the current scenario it is impractical to undertake manual mining because:-

- (i) The labours are not easily available;
- (ii) Manual mining cannot be undertaken in systematic and scientific manner as compared to mechanical mining which can be undertaken systematic/ scientific and controlled mining.
- (iii) In case of manual mining to achieve desired level of production more number of manpower would be required meaning thereby human interface within river bed area would increase and more ecological damage would be caused.

5.6 The method of mining even otherwise can not be uniform even for same area and all the methods have their own pros and cons, however, considering the current scenario wherever feasible mechanized (semi-mechanized or mechanized is same thing) mining should be preferred over manual method.

6. General Regulation relating to Mining

6.1 As per prevailing State Rules the Mineral Concession holders are required to get a Mining Plan for the area prepared from a "Registered Qualified Persons". The mining plan includes the area specific details along with the Mine Closure Plan (Progressive & Final) taking into consideration the details of the Geology and lithology of the area including the estimated mineral reserves of the area. Proposed method of mining/ development of mines, use of explosives and blasting operations, if any, stacking and disposal of minerals, mine-drainage pattern, handling of the overburden, location of weigh bridges, and mineral processing, if any. The extent of manual mining or mining with the use of machinery and mechanical devices along Level of Production (production from year-to-year for a period of five years), Mechanization, Type of Machinery to be used, nature and extent of the mineral body/ spot or spots where the mining operations are proposed to be undertaken; natural water courses, limits of mineral reserves and other forest areas and density of trees, if any, assessment of impact of mining activity on land surface and environment including air and water pollution i.e. the

environment management plan. In addition to this Mining plan also suggests the details of scheme of restoration/ rehabilitation of the area through afforestation, land reclamation, use of pollution control devices and such other measures as may be directed by the State Government from time to time.

- 6.2 The Mining Plan are to be got approved from the authorized officer of the State Government. Based on mining plan prior environmental clearance from the competent authority as per provisions of EIA Notification dated 14.09.2006 of MoEF & CC, GoI is obtained.
- 6.3 After obtaining the Environmental Clearances, to comply with requirement of Air Act, 1981 the Consent to Establish and "**Consent to Operate**" from State Pollution Control Board are also obtained before actual mining
- 6.4 The above said provisions mainly relates to mineral conservation and environmental protection. With regards to provisions related to safety in mines and welfare of labours provisions under the Mines Act, 1952 are ensured by the Directorate General Mines Safety, a department under the Ministry of Labour, Government of India.

7. Areas selected for Mining in District Yamuna Nagar

Background

- 7.1 As per rough estimate total area of rivers beds (all rivers and tributaries/rivulets) passing through district Yamuna Nagar is about **28 to 30 sq. km.** Further approximately about 90 sq km. area outside river bed is also having mineral deposits. A larger part of which is otherwise under various uses including agriculture. As regards selection of area for mining it may be pointed out that:-
 - (i) Earlier, (about 16-18 years back) mineral concession/mining contracts were being granted on revenue estate basis (without giving any specific details of areas), subject to various restrictions. The mineral concession holders used to undertake mining in areas after leaving restricted area.
 - (ii) Initially about **120 villages** were being offered for mining, however, over a period of time the number of villages/quarries reduced to about **67**, as area of some of the villages came under other

- restrictions either because of construction of some bridges on river bed or due to other development projects including habitation.
- (iii) The mode of grant of mining contracts of individual quarries/revenue estates in Yamuna Nagar district was changed in late nineties and instead granting individual quarries on contract, number of adjoining quarries were clubbed for the purpose of granting mineral concession. This mode was further changed and all minor mineral quarries of the district were given "as one unit". In this way they used to be a single contractor for all minor mineral quarries "**district as one unit**". In district Yamuna Nagar last such contract for "**district as one unit**" was granted on 11.04.2004 for a period up to 31.03.2009.
- (iv) Needless to state that such **mineral concession areas** used to have even the areas having no mineral deposits, the areas otherwise not permissible for mining. The mineral concession holders were under obligation to undertake mining only in the areas free from all restriction and as per prevailing Rules and Regulations. Mineral Concessions for minor Mineral prior to 14.09.2006 were not required to obtain environmental clearance.
- (v) The EIA notification dated 14.09.2006 became applicable for fresh contacts/ leases and in the year 2008 for grant of mineral concessions in respect of other areas in the State fresh auctions were notified subject to condition that mining will be allowed to be undertaken only after prior environmental clearance is obtained as per requirement of EIA notification dated 14.09.2006 of MoEF & CC, GoI. However, said condition was challenged by some prospective bidders on the plea that the notification dated 14.09.2006 was not applicable for mining of minor minerals.
- (vi) The operation of notification dated 14.09.2006 for mining of minor mineral was stayed by the Hon'ble Punjab and Haryana High Court vide its interim order dated 07.04.2008 in CWP No. 4578 of 2008- Chandi Mandir Stone Crusher Consumer Company Vs. Union of India and Others.

- (vii) The State could not have granted long term contracts during the pendency of said case because operation of the notification was under stay and in case long term contracts were granted the mineral concession holders would have claimed that at the time of grant the notification was not applicable for them or may have sought to cancel the contract.
- (viii) Subsequently, the Hon'ble High Court on 15.05.2009 while disposing of the above said writ petition (along with CWP no 20134 of 2004 Vijay Bansal v/s State) upheld that notification dated 14.09.2006 was applicable for mining of minor minerals also.
- (ix) However, as regards the process of obtaining the prior environmental clearance, the Hon'ble High Court directed the process to be followed in two parts. In the first stage, it was directed that the state of Haryana would submit the ToRs to the EAC and the EIA report will be prepared by Expert Appraisal Committee (EAC) in the MoEF, GoI before conducting the auctions. Subsequent to the holding of the auctions, the successful bidder shall obtain the prior environmental clearance from the competent authority.
- (x) The Hon'ble High Court, considering that some time would be required for completing the process as per above, and general public would face problems due to sudden closure of mining, permitted mining without environmental clearance for the period up to 28.02.2010.
- (xi) Accordingly, no long term contract in Yamuna Nagar area could be granted due to above litigation and after expiry of the last contract the mining operations was allowed in district Yamuna Nagar (as well as in other part of the state) for the period of up to 28.02.2010 without environmental clearance as per orders of Hon'ble High Court.
- (xii) However, the order dated 15.05.2009 of Hon'ble High Court relating to preparation of EIA report by the State Government was not acceptable to the MoEF, CC, GoI. The MoEF was of the view

that state being regulating agency cannot prepare the said report at its own. Therefore, the applications submitted by State of Haryana for approval of ToR were not considered.

- (xiii) The MoEF initially filed a Review Application before the Hon'ble High Court and thereafter SLP before the Hon'ble Supreme Court. During the pendency of said matter the state of Haryana neither could take further action relating to preparation of EIA report nor could auction its minor mineral areas for grant of mineral concessions subject to condition that Environmental Clearance shall be obtained by the project proponent.
- (xiv) The mining in district Yamuna Nagar /other parts of the State came to a grinding halt on 01.03.2010. The mining in the district Yamuna Nagar remained closed. The mining operations prior to 01.03.2010 were either undertaken by the contactors to whom contract was granted prior to 14.09.2006 or under special dispensation granted by the Hon'ble High Court to operate mines without Environment clearance till 01.03.2010.
- (xv) Subsequently, the Hon'ble Supreme Court on 28.10.2013 while disposing of the SLP No. 729 of 2011 of the MOEF & CC, GoI held that prior environmental clearance is to be obtained by the concerned mining lease holders and not by the State Government. In other words the process for obtaining prior environmental clearance was to be followed as prescribed by MoEF, CC, GoI under its notification dated 14.09.2006 as amended to time to time (uniformly applicable for country).
- (xvi) In view of above the State of Haryana in November, 2013 could issue notifications for grant of mineral concessions in various parts of the State including district Yamuna Nagar through open auctions to be held in December, 2013.

8. Areas Selected for mining in November/ December, 2013 and thereafter (the areas at present on contracts or to be granted on mining contracts)

- 8.1** In November, 2013 it was decided that instead of the auctioning all of minor

- mineral quarries of a district as a single unit, the same should be granted in the form of big mining units. The mineral concessions for district as one unit were found to be resulting in monopoly of a few in the business of mining in a district.
- 8.2 At the cost of repetition it is stated that mineral concession areas of large size blocks/units used to have even such areas which otherwise were not permissible for mining. The restricted area were not meant to be used for actual mining operations but otherwise permissible for subsidiary activities like installation/establishment of check posts/weighbridge etc.
- 8.3 In December, 2013 a total of 16 Mining Blocks having contiguous area were carved out and were auctioned as 06 separate units (one unit was having number of blocks) having total area of 3601.62 hectares. The said mineral concessions were granted subject to condition that mining would be allowed to be commenced only after prior environmental clearance is obtained by the concerned mining contracts/LoI holders.
- 8.4 The areas of each of these Mining Units except that of Unit No. 1 & Unit No. 2 are very large. However, subsequently 04 of the LoI holders got their bids cancelled through Hon'ble High Court. The area of such cancelled 04 large size contracts became available for fresh grant. It was decided to be auctioned afresh by carving our small size blocks as compared to large size areas auctioned in the December, 2013.
- 8.5 The area available for actual mining out of area of above said 04 units and a few of other areas which earlier could have been offered due to some issues relating to access road etc., were notified for fresh grant by carving out **33 Mining Blocks**. While auctioning comparatively smaller blocks the total area available for grant of mineral concession got further reduced to **1221.91 hectare**.
- 8.6 At Present 02 big Mining Units and 31 Mining Blocks, having total area of 1825 hectare have already attracted bids in auction/e-auctions.

9. Annual Capacity of Areas selected for mining of minor minerals

- 9.1 In order to make estimates of mineral deposits and mineable reserves of any mineral a detailed exploration is required to be undertaken. The economic life

of a mine based on the mineral estimates including current mining production plans are made on the basis of study taking into consideration the quantity and quality of the minerals extracted during the reporting time, changes in Economic Viability due to changes in prices and costs, development of relevant technology, newly imposed environment or other regulations, and data on exploration conducted concurrently with mining. It presents the current status of the deposits, providing a detailed and accurate, up-to-date statement on the reserves and the remaining resources.

- 9.2 However, in case of minor minerals like Boulder, Gravel and Sand as the same are available in abundance and estimates can be made on the basis of mineral seen at surface or through the area operated in past and on the basis of permissible limits to excavate minerals.
- 9.3 The minerals are non-renewable resources, however, minor minerals found in the river bed areas have peculiar condition relating to mineral reserves. The minerals removed from the river bed areas get replenished after every rainy season with minerals brought along with water from hilly areas. The mineral reserves for mining on replenishment remain almost same every year after rainy season.
- 9.4 On the other hand in case of areas outside river bed or any area used for mining, the mineral reserves reduce after every year after mining operations. Hence, total mineable reserves after mining gets depleted and the life of any mine also reduces. This is a normal practice for mineral reserve estimation for all types of mining activities other than river bed areas.
- 9.5 The mineral reserves for river bed areas are calculated on the basis of maximum depth of 3 meters. The area multiplied with depth gives volume and volume multiplied with bulk density gives the quantity in M.T. In case of river bed areas per hectare area, maximum availability of mineral for actual mining is 60,000 MT. However, as explained above the mineral excavated from river gets replenished after every year, therefore, the same quantity remains available for mining again and again.
- 9.6 In case of areas outside river bed the maximum depth of 9 meters from ground level is considered for calculation of capacity of a mine. The area multiplied with 09 gives the volume and volume multiplied with bulk density gives quantity of total mineral available in M.T. However, on an average half

meter to 1 meter layer is of ordinary earth, so actual mineral can be excavated up to maximum depth of about 08 meters per hectares area outside river bed in general provides 1,60,000 M.T. of mineral.

10. Capacity of Minor Mineral Mines/ Areas selected for mining

10.1 The capacity of any mining area mainly depends upon of mineable reserves, economical viability and demand of minerals. In most of the cases particularly in respect of minor minerals the mineral deposits are found in huge quantity. However, the demand of material depends upon other factors such as ongoing infrastructure projects and other related private constructions. The operation of other minor mineral mines in and around any area/mine is one of the important factors affecting the production plan.

To illustrate for example if total demand of particular area for construction material is "X" M.T. per annum, all operating mines in and around any particular area depending upon market forces would be supplying the material. Accordingly if operation in any of the mines stops, the demand of the market would be met by the remaining operating mines. In other words the production level of operating mines shall increase. The annual production plan is prepared by mining contractors/lease holders considering their maximum capacity. However, in all cases peak capacity in general may or may not be achieved at any point of time.

10.2 As per documents submitted by the Mineral Concessionaires maximum annual capacity of each of the 35 Mining Units/Blocks of District Yamuna Nagar, are given as under :

Sr. No.	Mining Unit/Block Location	Area (In Hect.)	Period (In yrs)	Name of Minor Minerals	Status of Granted of Mineral Concession	Annual Capacity as per EC/Mining Plant/TOR in lakh MT.	Present Status
Riverbed Mining Areas							
1.	Yamuna Nagar Unit-1 (Tajewala)	48.97	10	Gravel, Sand, Boulder	Yes	20.64	Yet to be Auctioned

Sr. No.	Mining Unit/Block Location	Area (In Hect.)	Period (In yrs)	Name of Minor Minerals	Status of Granted of Mineral Concession	Annual Capacity as per EC/Mining Plant/TOR in lakh MT.	Present Status
2.	Yamuna Nagar Unit-2 (28 village)	554.13	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	120.00	Working
3.	Bailgarh- South Block (YNR-B2)	28.00	9	Gravel, Sand, Boulder	Yes	13.00	Working
4.	Bailgarh North Block (YNR-B1)	44.00	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	21.44	EC/CTO Awaited
5.	Mandoli Ghaggar East Block (YNR B3)	20.18	10	Gravel, Sand, Boulder	Yes	8.58	Working
6.	Mandoli Ghaggar West Block (YNR B4)	25.56	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	11.91	Working
7.	Kanalsi Block (YNR B5)	44.14	09	Gravel, Sand, Boulder	Yes	19.50	Working
8.	Jairampur Jagir Block/YNR B6	33.58	10	Gravel, Sand, Boulder	Yes	15.20	EC/CTO Awaited
9.	Beer tapu Block (YNR B7)	14.45	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	6.15	Working
10.	Odhari North Block YNR-B8	10.00	9	Sand	No	4.50	Area under Consideration
11.	Odhari South Block YNR-B9	56.98	10	Sand	No	25.18	Area under Consideration
12.	Lapra Block/ YNR B10	34.28	7	Sand	Yes	15.30	EC/CTO Awaited
13.	Pobari Block (YNR B11)	23.05	9	Sand	Yes	11.00	Working
14.	Gumthala I North Block(YNR B16)	44.62	7	Sand	Yes	21.00	Working
15.	Gumthala South Block/YNR B-	49.67	09	Sand	Yes	21.88	Working
16.	Jathlana Block /YNR b12	101.27	10	Sand	Yes	36.00	Working

Sr. No.	Mining Unit/Block Location	Area (In Hect.)	Period (In yrs)	Name of Minor Minerals	Status of Granted of Mineral Concession	Annual Capacity as per EC/Mining Plant/TOR in lakh MT.	Present Status
17.	M T Karhera Block/ YNR B-13	67.79	07	Sand	Yes	29.60	EC/CTO Awaiting
18.	Nagla Rangraan/ YNR B-14	89.48	9	Sand	Yes	38.60	EC/CTO Awaiting
19.	Nagli Block/ YNR B-15	77.25	10	Sand	Yes	33.30	EC/CTO Awaiting
20.	Dhanora Block/ YNR B-18	18.18	10	Sand	No	9.38	Yet to be Auctioned
		Totl.= 1385.58				Totl.=482.16	
Outside Riverbed Mining Areas							
21.	Bhood Kalan (YNR B19)	12.62	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	2.59	Temp. Closed Due to
22.	Bhood Majra (YNR B20)	9.95	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	2.00	Temp. Closed Due to
23.	Kohliwala (YNR B21 & 22)	13.59	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	2.50	Working
24.	Devdhar (YNR B24)	31.87	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	5.10	Working
25.	Malikpur Khadhar Block/YNR B-28	23.20	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	4.00	Working
26.	Pipli Majra Block/ YNR B29, 30 & 31	18.20	7	Gravel, Sand, Boulder	Yes	3.70	Working
27.	Jaidhari Block/ YNR B-33	48.60	08	Gravel, Sand, Boulder	Yes	9.10	Working
28.	Mandewala (YNR B-38)	15.00	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	22.80	EC/CTO Awaiting
29.	Chuharpur Block/YNR B-26&27	50.40	08	Gravel, Sand, Boulder	Yes	74.56	EC/CTO Awaiting

Sr. No.	Mining Unit/Block Location	Area (In Hect.)	Period (In yrs)	Name of Minor Minerals	Status of Granted of Mineral Concession	Annual Capacity as per EC/Mining Plant/TOR in lakh MT.	Present Status
30.	Begampur (YNR b-37)	39.50	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	56.88	EC/CTO Awaited
31.	Jaidhar Block /YNR B-34	25.60	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	36.86	EC/CTO Awaited
32.	Nandgarh Block /YNR B36	29.60	8	Gravel, Sand, Boulder	Yes	46.22	EC/CTO Awaited
33.	Ismsilpur Block/YNR B32	50.50	08	Gravel, Sand, Boulder	Yes	76.96	EC/CTO Awaited
34.	Haldari Gujjar Block/YNR B-35	46.80	08	Gravel, Sand, Boulder	Yes	70.43	EC/CTO Awaited
35.	Galauri Block/ YNR B 39	24.00	08	Gravel, Sand, Boulder	Yes	4.40	Working
	Total= 439.43					Total= 418.1	
	G. Total area = 1825.01 hect.					G. Total=900.26	

10.3 The annual capacities of above mines have been ascertained on the basis of area available for mining and production plans suggested by the mineral concession holders under their Mining Plan/ Application for seeking Environment clearance. In case of the areas not granted till now, the average reserves had been taken into account. Further, the annual capacity of river bed areas is calculated on the basis of assumption that the quantity lifted during any year would get replenished after every rainy season. Whereas the capacity of areas outside river bed has been calculated on the basis to total mining reserves to be excavated during the period of mineral concession.

10.4 That as explained in for forging paras the demand of mineral is most crucial factor in deciding the actual production of any mine or area. In case of district Yamunanagar, the operation of minor mineral mines towards

Saharanpur side of U.P also has direct bearing. The total demand of mineral in these areas can be estimated on the basis of past production of minor minerals. During last 10 years the production of minor minerals excavated are tabulated as below:-

Year	Boulder/Gravel/Bajri	Sand	Total
1999-2000	8,68,970	2,44,100	11,12,070
2000-2001	9,81,050	3,02,100	12,83,150
2001-2002	12,30,050	4,66,700	16,96,750
2002-2003	37,43,286	10,40,300	47,83,586
2003-2004	25,40,800	-----	24,40,800
2004-2005	13,52,008	7,58,800	21,10,808
2005-2006	23,13,476	14,67,252	37,80,728
2006-2007	11,81,600	14,46,000	26,27,600
2007-2008	14,23,000	14,07,000	28,30,000
2008-2009	12,15,000	12,88,000	25,03,000
Total	1,68,49,240	63,67,052	2,52,69,492
Average	16,84,924	6,36,705	25,26,949

The perusal of above would show that on an average about 25 lakh M.T. minor mineral per annum was being excavated from minor mineral mines of district Yamunanagar. Most of the excavation is undertaken in the river bed areas where minerals excavated get replenished after rainy season due to fluvial action. Even annual demand after 2008-09, is considered to have been accelerated with a rate of 10% every year, the demand for present shall about 45-50 lakh M.T. per year. Approximately 75% of the minerals are likely to be excavated from river bed areas. Accordingly, it is estimated that about 25-30 lakh M.T. would be excavated from various parts of river bed areas, spread over approximately 1385 hectare having estimated capacity of 482 lac MT per annum. The requirement would be less than 10% of the annual capacity of all river bed areas used for actual mining.

The quantity of actual mineral to be excavated even remains at optimum level, the replenishment rate is still higher. Though there is no specific study available on the quantity of sedimentation/ replenishment but the same is directly proportionate to the area of catchments, Geological formation of the area of catchments, gradient and water flow of the river etc. The area in question is situated in the foothills of Shivalik range, being very young in Geological formation. The region is extremely important because it is the prime source of sediments, with a number of steep gradient torrents transport downstream to the

plan. The huge quantity of boulder and gravel settles immediately after reaching plane areas and thereafter fine sand gets deposited. The department is planning to study annual replenishment rate by taking time to time MRL readings of river bed areas.

11. DETAILS OF ROYALTY/REVENUE RECEIVED IN LAST THREE YEARS.

Sr.	Year	Revenue (In Rs)
1	2014-15	NIL (Mining Closed)
2	2015-16	NIL (Mining Closed)
3	2016-17	24,74,22,307/-

12. DETAILS OF PRODUCTION OF MINOR MINERAL OF LAST THREE YEARS.

Sr.	Year	Production (In MT)
1	2014-15	NIL (Mining Closed)
2	2015-16	NIL (Mining Closed)
3	2016-17	13,68,302-00

13. PROCESS OF DEPOSITION OF SEDIMENTS IN THE RIVER OF DISTRICT.

The deposition in a river bed is more pronounced during rainy season although the quantum of deposition varies from stream to stream depending upon numbers of factors such as catchment, lithology, discharge, river profile and Geomorphology of the river course. It has been observed that during rainy season all of the pits created due to excavation of minerals are completely filled up and as such the excavated area is replenished with new harvest of minerals.

In order to calculate the mineral deposits in the stream beds, the mineral constituents have been categorized as Clay, Silt, Sand, Gravel and Boulder. However during present calculation, the waste material i.e silt, clay which vary from 10 to 20% in different streams have been included in the total production. The mineral reserves have been included only upto 1.00 meter depth although there are some portions in the river beds such as channel bars, point bars and central islands where the annual deposition is raising the level of river bed thus causing shifting of the rivers towards banks resulting in to cutting of banks and at such locations, removal of this material upto the bed level is essential to control the river flow in

its central part to check the bank cutting. While calculating the mineral potentials, the mineral deposits lying in the sub-tributaries of that particular stream/river has not been taken into consideration. Since these mineral deposits are adding annually to the main river, the mineral deposits will be much more.

The important rivers/streams of the district are Yamuna, Somb, Boli, Sarasvati, Chautang, Rakshi, etc. Yamuna River rises from the snow-clad peaks of the middle Himalayas at Yamnotri, enters the district from its northeastern corner through a narrow corridor in the Siwaliks. River Yamuna enters plain area for the first time from Yamuna Nagar and running through the district which forms the eastern boundary with the neighboring District Saharanpur. This boundary is also a state boundary. The Somb river originates in the Shivalik hills near Adi Badri in Yamuna Nagar district on the border of Haryana and Himachal Pradesh State. Boli nadi joins the somb nadi near the Dadupur and after combining both nadi's join the Yamuna river at Mehar majra. The Historical river Saraswati also originates from the place named Adibadri in the district. The rakshi stream takes its birth in the rolling foot hill plains while the Chautang and Sarasvati rivers originate in the lower hills. Generally, the slope of the district is from north-east to south-west, in which direction of most of rivers/nadis/rainfed torrents flow down. The Higher area that is not flooded in rainy season is called Bangar and the lower flood prone area is called Khaddar.

14. GENERAL PROFILE OF THE DISTRICT.

Country	India
State	Haryana
Headquarters	Yamunanagar
Sub Divisions	Jagadhri, Bilaspur, Radaur
Tehsils	Jagadhri, Chhachhrauli, Bilaspur, Radaur
Sub Tehsils	Sadaura, Mustafabad, Khizrabad
Area	1,756 Sq. km (678 sq mi)
Population (2001)	
• Total	12,14,162
• Density	590/sq. km (1,500/sq mi)
Demographics	
• Sex ratio	862

15. LAND UTILIZATION PATTERN IN THE DISTRICT.

In District Yamuna Nagar, most of the areas are utilized for Agriculture and Horticulture, some area is used for Mining and rest of land is forest.

16. PHYSIOGRAPHY OF DISTRICT.

The district is divided into four Physiographic units:-

- Siwaliks
- Dissected Rolling Plains
- Interfluvial Plains
- Active and Recent Flood Plains
- Relict Plains

Siwaliks hills – Siwalik hill ranges occupy the northern fringe of Yamuna Nagar district and attain the height up to 950m AMSL. The hills are about 500m high with respect to the adjacent alluvial plains. These are characterized by the broad tableland topography that has been carved into quite sharp slopes by numerous ephemeral streams come down to the outer slopes of the Siwaliks and spread much of gravels boulders, pebbles in the beds of these streams.

Kandi Belt – A dissected rolling plain in the northern parts of district is a transitional tract between Siwalik Hills and alluvial plains. It is about 25 km wide and elevation varies between 250 and 375m AMSL.

Interfluvial plains – This tract is part of higher ground between Ghaggar and Chautang and includes high mounds and valleys. In general, the slope is from northeast to southwest.

Active and recent flood plains – This plain is narrow tract along river Yamuna in the district.

Relict wedge plain – This is almost in alignment to the surface water divide between the westward flowing Ghaggar and eastward flowing Yamuna River.

17. Rainfall data:- Months Wise

Monthly Normal Rainfall Averages of 5 year (2011-15) in Milimetre

Sr. no.	Month	2011-15
1	January	32.5
2	February	46.5
3	March	28.9
4	April	10.0
5	May	20.5
6	June	182.0
7	July	268.0
8	August	331.0
9	September	108.6
10	October	14.0
11	November	12.6
12	December	20.6
	Total	1075.2

18. GEOLOGY AND MINERAL WEALTH:-

The north-eastern and central part of Haryana is predominantly characterized by sedimentary lithology in the sub-Himalayan zone comprising Subathus, Dagshais, Kasaulis and Siwaliks. A general Regional Stratigraphic sequence in the area is given in the table.

Table: Regional Stratigraphic sequence

Age	Super Group	Group	Formation	Lithology
Holocene			Newer alluvium and Newer Aeolian Deposits	Gravel, Sand, Silt, Clay, Limestone, gypsum
Lower to upper Pleistocene			Older alluvium and older Aeolian deposits	Gravel, grey sand, silt clay brown sand, calcrete
Lower to Middle Pleistocene		Upper Siwalik	Boulder Conglomerates formation	Conglomerate, sand stone, silt. Clay
Upper Pliocene			Pinjore Formation	Coarse grit, red sand stone and clay,

				conglomerate
			Tat rot formation	Friable Sand Stone and variegated clay
	Middle Siwalik		Dhokpathar Formation	Brown Sandstone and variegated clay
			Nagri Formation	Hard grey sand Stone and minor shale
	Lower Siwalik		Nahan Formation	Course gritty, clay and red sandstone often calcareous, brownish shale with lignite lenticels greenish white quartzite
Lower Miocene	Sirmur		Kausauli Formation	Grey and stone, green shale and grey clay
			Dagsai Formation	Purple sand green sand stone, deep red gritty, clay, white sand stone with ferruginous concretions
Upper Eocene			Subathu Formation	Sandstone with grit clay. Impure fossiliferous limestone calcareous slate, greenish shale and dark brown quartzite
Pre-Proterozoic			Tunda pathar	Tickly bedded, stromatolite limestone with carboniferous shale and quartzite

19. District wise detail of river/stream and other sand sources:

S. No.	Name of River	Origin	End C.G. in	Width	Length in Ynr Distt.	Remarks
1	Yamuna River	Origin in Haryana	Gumthala	0.6KM	70KM	
2	Somb Nadi	Ranjitpur	Dadupur	0.06 KM	40KM	Meet in Dad

20. List of villages where minor minerals (Gravel, Boulder and Sand) are available.

- As per above at the para no. 10.2

21. Drainage system with description of main rivers

S. No.	Name of the river	Area drained (Sq. Km)	% Area drained
1	Yamuna River (1376 km)	21265	6.5

21.1 Salient Feature of Important Rivers and Streams:

S. No.	Name of the River or Stream	Total Length in the District (in Km)	Place of origin	Altitude at Origin
1	River Yamuna	70 Km	Yamnotri	3291 mts Or 10797 feet
2.	Somb Nadi	50 Km	Ranjitpur	

Portion of the River or Stream Recommended for Mineral Concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)
50 km	70	400 meters	2,40,00,000 Sqm	540 lakh MT

Mineral Potential

Boulder, Gravel, Sand (In lakh MT)	Sand (In lakh MT)	Total Mineable Mineral Potential (MT)
654.52	245.74	900.26

Annual Deposition

	236.42	245.74	482.16
--	--------	--------	--------

S. No	River or Stream	Portion of the river or stream recommended for mineral concession	Length of area recommended for mineral concession (in kilometer)	Average width of area recommended for mineral concession (in meters)	Area recommended for mineral concession (in square meter)	Mineable mineral potential (in metric tonne) (60% of total mineral potential)

Total for the District	50 KM	70 KM	400	2,40,00,000 Sqm	540 MT	

22. Reclamation and Restoration of mining area and provision of Fund for the same:

22.1 As explained in foregoing paras mining in river bed areas takes place only up to a maximum depth of 3 meter from existing river bed level, that too in central 3/4th of the river bed. The material brought by the river due to fluvial action fills the void created in the process of excavation. In this way the area operated/ used for excavation of mineral from rivers gets reclaimed after every rainy season. Further, in the river bed areas there are no flora and fauna. Accordingly as such river bed mining does not create any ecological impact. The excavation of minerals from central part of the river in fact provides void/space for settlement of sediments without raising the river bed level.

22.2 As it is well known that rising of bed level results in river meandering (change of course) and in the present day the change of course of any river results in floods and damages. Though sometimes areas in and adjoining river banks are affected because of unforeseen circumstances/water stream due to heavy rains.

22.3 Further, the area outside river bed requires levelling reclamation and restoration after mining. The land owners take compensation from the mining contractors in lieu of surface rights. The areas after mining are levelled by the contractors or land owners (depending upon mutual settlement between the contractor and land owners) to make the land reusable for cultivation. In order to ensure that areas after mining in case needs reclamation/restoration are properly dealt/restored.

22.4 The State Rules, 2012 appropriately provide provisions of R&R Fund namely "**Mines and Mineral Development, Restoration and Rehabilitation Fund**". The mineral concession holders are liable to deposit an amount equal to 10% of the dead rent or royalty or contract money paid to the state for Restoration and Rehabilitation works. Further, the state also contributes 5% of the amount received by it on account of the dead rent or royalty or contract

money in a financial year to the Fund. The Fund has been created only for funding of the restoration or reclamation or rehabilitation works in the sites affected by mining operations. The Fund can be used for creating common facilities for the benefit of community in and around areas where mining activities are undertaken, development of infrastructure facilities for orderly growth of the mining operations and allied activities and other related works/schemes.

22.5 In compliance with amendment in the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957, vide which Section 9B has been inserted making it mandatory to form District Mineral Foundation (DMF) in each district, the State has recently (19.12.2017) notified Haryana District Mineral Foundation Rules-2017. The Foundations shall work for welfare and benefit of persons and areas affected due to mining operations. 1/3rd of the amount collected in **“Mines and Mineral Development, Restoration and Rehabilitation Fund”** shall be transferred in the **DMF Fund**. The projects to be carried out under **Pradhan Mantri Khanij Kshetra Kalyan Yojna** shall be implemented by the District Mineral Foundations.

22.6 The areas operated in past in the district Yamunanagar were restored (river bed filled up with sediments brought by fluvial action and areas outside river bed levelled by land owners for cultivation). However, some of the areas used for mining in land falling outside river bed were not put in use by private land owners after mining for the reasons known to them. The private land owners could not have been insisted for undertaking cultivation, in case they don't choose for the same. A few of the patches of such un-reclaimed areas are existing in and around crusher zone areas in village Ballewala, Diowala, Mandewala and Kohliwala. In this area over a period of time some rain water get collected and remains wet for quite long every year. The same had no ecological impact on the ecology of the area. As a matter of fact such areas are acting as water recharge zone as well as wet land.

Conclusion:

In district Yamunanagar a total of 1825.01 hectare area has been identified for mining of minor minerals under 35 mineral concessions (at para 10.2), though

STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY HARYANA
Bay No. 55-58, Prayatan Bhawan, Sector-2, PANCHKULA.

No. SEIAA/HR/2016/475

Dated: 27.06.2016

To

M/s Mubarikpur Royalty Company,
Punjab Stone Crusher, Mubarikpur-Ramgarh Road,
VPO-Mubarikpur, District-Mohali (Punjab)

Subject: Environmental Clearance for Mining of Boulder, Gravel and Sand (Minor Minerals) Mines namely "Bailgarh South Block/YNR B2" over an area of 28.00 Ha. Falling in Village-Bailgarh, Tehsil-Chhachhrauli, District Yamuna Nagar, Haryana.

This has reference to your application transferred online by MoEF & CC, GoI to M. S. SEIAA on 16.04.2016; hard copy received on 21.04.2016 and subsequent letter dated 01.06.2016 seeking prior environmental clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 and subsequent amendments on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., Form-1, Pre-feasibility report, copy of approved Mining Plan, EIA/EMP on the basis of approved TOR and the additional clarifications furnished in response to the observations of the EAC of MoEF & CC, GoI and State Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted by MOEF & CC, GOI vide their Notification 21.08.2015, in its meetings held on 06.05.2016 and 01.06.2016.

[2] The EAC/SEAC has examined the application and noted that the proposal is for Mining of Boulder, Gravel and Sand (Minor Minerals) Mines namely "Bailgarh South Block/YNR B2" Falling in Village-Bailgarh, Tehsil-Chhachhrauli, District Yamuna Nagar, Haryana over an area of 28.00 Ha. The Mines & Geology Department Haryana has granted for an area of 28.00 Ha "Bailgarh South Block/YNR B2 at Village-Bailgarh, Tehsil-Chhachhrauli, District Yamuna Nagar, Haryana vide LOI dated 19.06.2015. The project proponent has submitted approved mining plan dated 23.02.2016. The public hearing was conducted by HSPCB on 09.03.2016. The EAC/SEAC has appraised this project as category B-1 NOC from Forest Department has been obtained.

Brief details of the project:

1.	Category/Item no. (in schedule):	1 (a) B-1	
2.	Location of Project	Village-Bailgarh, Tehsil-Chhachhrauli, District Yamuna Nagar, Haryana	
3.	Project Details Khasra No.	Mining of Boulder, Gravel and Sand (Minor Minerals) Mines namely "Bailgarh South Block/YNR B2" over an area of 28.00 Ha.	
	Production capacity	13,00,000 TPA @173 Trips/day (25 MT)	
4.	Project Cost	8.50 Crore	
5.	Water Requirement & Source	43 KLD through Tankers	
		Dust suppression	25 KLD
		Plantation	15 KLD
		Drinking	3 KLD
6.	Environment Management Plan Budget	34 lakh	
7.	CSR Activates Budget	20 Lakh	
8.	Production	The proposed production for the five years is @ 13,00,000 TPA. The ultimate pit limit is 3 m bgl or 2 meter above water table which ever comes first.	
9.	Corner Coordinates of the lease area	Co-ordinator	Latitudes
		Lease area	Longitudes
			N 30° 13' 29.01" E77° 30' 34.59"
			N 30° 13' 10.29" E77° 30' 24.22"
			N 30° 12' 41.01" E77° 30' 17.97"
10.	Green belt/ plantation	Year of Plantation	Proposed Plantation
		I Yr.	1000 Trees
		II Yr.	1000 Trees
		III Yr.	1000 Trees
		IV Yr.	1000 Trees
		V Yr.	1000 Trees
11.	Machinery required	Excavator, JCB, Tipers/Trucks, Water Tanker Light Vehicles/Geep and Maintaniance Van	

The Authority in its 92nd meeting held on 15.06.2016 decided to agree with the recommendations of SEAC to accord Environment Clearance to this project by imposing the following conditions:-

A SPECIFIC CONDITIONS:

- [1] This Environment Clearance is granted for the proposed production of Boulder, Gravel and Sand (Minor Minerals) for the five years @ 13,00,000 TPA. The ultimate pit limit is 3 m bgl or 2 meter above water table which ever comes first.

Co-ordinator	Latitudes	Longitudes
Lease area	N 30 ⁰ 13'29.01"	E77 ⁰ 30'34.59"
	N 30 ⁰ 13'10.29"	E77 ⁰ 30'24.22"
	N 30 ⁰ 12'41.01"	E77 ⁰ 30'17.97"

- [2] The project proponent shall carry out mining activity strictly as per the approved Mining Plan.
- [3] Environmental Clearance is subject to obtaining clearance, under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the National Board of Wildlife, as applicable to the project.
- [4] No mining activities will be allowed in forest area, if any, for which the Forest Clearance is not available.
- [5] The Project proponent shall obtain consent to Operate from the State Pollution control Board, Haryana and effectively implement all the conditions stipulated therein.
- [6] Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular and Periodical medical examination of the workers engaged in the project and records maintained; also, Occupational health check-ups for workers having some ailments like BP, diabetes, habitual smokers, etc. shall be undertaken once in six months and necessary remedial/preventive measures taken accordingly. Recommendations of National Institute for labour for ensuring good occupational environment for mine workers would also be adopted.
- [7] Project Proponent shall appoint a Monitoring Committee to monitor the replenishment study, traffic management, levels of production, River Bank erosion and maintenance of Road etc.

- [8] The number of trips of the trucks shall not exceed 173 Trips/day (25 MT). Transport of minerals shall be done either by dedicated road or it should be ensured that the trucks/dumpers carrying the mineral should not be allowed to pass through the villages.
- [9] Project Proponent shall ensure that the road may not be damaged due to transportation of the mineral; and transport of minerals will be as per IRC Guidelines with respect to complying with traffic congestion and density.
- [10] Excavation will be carried out up to a maximum depth of 3 meters from surface of river bed one meter above from the ground water level of the River channel whichever is reached earlier.
- [11] The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled & water sprinkling will also be done regularly. Vehicles with PUC only will be allowed to ply. The mineral transportation shall be carried out through covered trucks only and the vehicles carrying the mineral shall not be overloaded. Project should obtain 'PUC' certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centre.
- [12] Washing of all transport vehicles should be done inside the mining lease.
- [13] Permanent pillars have to be constructed to demarcate width of extraction of Reserve of Minerals leaving 25% of River width from the bank with depth of 1.5m below the ground and 1.2 m above the ground to observe its stability.
- [14] There shall be planning, developing and implementing facility of rainwater harvesting measures on long term basis in consultation with Regional Director, Central Groundwater Board and implementation of conservation measures to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board.
- [15] The Project Proponent shall also take all precautionary measures during mining operation for conservation and protection of endangered flora/fauna, if any, spotted in the study area.
- [16] Main haulage road in the mine should be provided with permanent water sprinklers and other roads should be regularly wetted with water tankers fitted with sprinklers.

- [17] Provision shall be made for the housing of construction for labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- [18] No River sand mining shall be allowed in flowing water and no mining is allowed in rainy season.
- [19] The project proponent shall submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity/ production levels shall be decreased/ stopped accordingly till the replenishment is completed.
- [20] The project proponent shall ensure that no natural water course/water body shall be obstructed due to any mining operations.
- [21] The dumping site selected and proposed shall be used for over burden dump at the designated site within the lease area as per the approved mine plan. In no case the overburden should be dumped outside the lease area.
- [22] Garland drains shall be constructed to prevent the flow of the water in the dumps.
- [23] Green belt should be developed as per the proposed plantation as given in the proposal. Plantation should be carried out in phased manner.
- [24] Regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of SPM and RPM such as haul road, loading and unloading point and transfer points. It shall be ensured that the Ambient Air Quality Parameters conform to the norms prescribed by the CPCB.
- [25] Regular monitoring of ground water level and quality shall be carried out in and around the mine lease. The monitoring shall be carried out four times in a year-pre monsoon (April-May), monsoon (August), post monsoon (November); winter (January) and the data thus collected may be sent regularly to MOEF Regional Office, Chandigarh and Regional Director CGWB.

- [26] Data on ambient air quality and stack emissions shall be submitted to Haryana Pollution Control Board once in six months carried out by MOEF/NABL/CPCB/ Government approved lab.
- [27] Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Measures shall be taken for maintenance of vehicles used in mining operations and in transportation of mineral. The vehicles shall be covered with a tarpaulin and shall not be overloaded. The project proponent shall ensure that the vehicle must have pollution under control certificate.
- [28] The project proponent shall take all precautionary measures during mining operations for conservation and protection of endangered fauna, if any, spotted in the study area. A plan for conservation shall be drawn and got approved from the Chief Wildlife Warden of the State before start of mining operations. Necessary allocation of funds for implementation of the conservation plan shall be made and the funds so allocated shall be included in the project cost. All the safeguard measures brought out in the wildlife conservation plan so prepared specific to the project site shall be effectively implemented. A copy of action plan may be submitted to the HSPCB and MOEF, Regional Office, Chandigarh within 3 months..
- [29] As envisaged, the Project Proponent shall invest at least an amount of Rs. 29.0 lakh per annum as cost for implementing various environmental protection measures including recurring expenses per year.
- [30] A sum of Rs. 20.0 Lakhs/annum shall be earmarked by the Project proponent for investment as CSR on socio economic up-liftment activities of the area particularly in the area of habitat, health or education, training programme of rural women & man provide the kit for employment generation. The proposal should contain provision for monthly medical camps, distributions of medicines and improvement in educational facilities in the nearby schools. Details of such activity along with time bound action plan be submitted to HSPCB/SEIAA Haryana before the start of operation.
- [31] Budgetary provision of Rs. 10.00 lakh per year earmarked for the labours working in the Mine for all necessary infrastructure facilities such as health

facility, sanitation facility, fuel for cooking, along with safe drinking water, medical camps and toilets for women, crèche for infants should be made and submitted to HSPCB at the time of CTE/CTO/SEIAA Haryana. The housing facilities should be provided for mining labours.

- [32] A Final Mine Closure Plan along with details of corpus fund shall be submitted to the SEIAA well within the stipulated period as prescribed in the minor mineral concession rules 2012..
- [33] The project proponent shall ensure that the EC letter as well as the status of compliance of EC conditions and the monitoring data are placed on company's website and displayed at the project site.
- [34] The project proponent shall ensure that loading in Trucks do not exceed the norms fixed by the Transport Department as per relevant rules.
- [35] The project proponent shall ensure approach roads are widened and strengthened as per requirements fixed by PWD and district administration before the start of the work.
- [36] The project proponent shall ensure supply of drinking water through RO.
- [37] The project proponent shall strictly adhere to the Sustainable Sand Mining Management guidelines issued by MoEF & CC, GoI on 15.03.2016 and shall ensure the compliance of the standard environmental conditions prescribed for the sand mining in the said guidelines; in addition to the conditions imposed in the environment clearance letter.
- [38] The project proponent shall carry out mining in semi mechanized manner using manpower, tractor, trucks, JCB and excavator for king transportation.

GENERAL CONDITIONS:

- [i] Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986.
- [ii] Any change in mining technology/scope of working shall not be made without prior approval of the SEIAA.

- [iii] Any change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall not be made.
- [iv] Periodic monitoring of ambient air quality shall be carried out for PM₁₀, PM_{2.5}, SO₂ and NO_x monitoring. Location of the stations (minimum 6) shall be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring shall be decided in consultation with the Haryana State Pollution Control Board (HSPCB). Six monthly reports of the data so collected shall be regularly submitted to the HSPCB/CPCB including the MOEF, Regional office, Chandigarh.
- [v] Personnel working in dusty areas shall wear protective respiratory devices they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- [vi] Occupational health surveillance program of the workers shall be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
- [vii] The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year wise expenditure shall be reported to the HSPCB and the Regional office of MOEF located at Chandigarh.
- [viii] The project proponent shall also submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated EC conditions including results of monitored data (both in hard copies as well as by e-mail) to the northern Regional Office of MoEF, the respective Office of CPCB, HSPCB and SEIAA Haryana.
- [ix] The above conditions will be enforced, inter alia, under the provision of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986 and the Public Liability Insurance Act 1991 (all amended till date) and rules made hereunder and also any other orders passed by the Honb'le Supreme Court of India High Court of Haryana and other Court of law relating to the subject matter.

- [x] The Project proponent should inform the public that the project has been accorded Environment Clearance by the SEIAA and copies of the clearance letter are available with the Haryana State Pollution Control Board & SEIAA. This should be advertised within 7 days from the date of issue of the clearance letter at least in two local newspapers that are widely circulated in the region and the copy of the same should be forwarded to SEIAA Haryana. A copy of Environment Clearance conditions shall also be put on project proponent's web site for public awareness.
- [xi] All the other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from the Chief Controller of Explosives, Fire department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 etc. shall be obtained, as may be applicable, by Project Proponent from the competent authority before the start of mining operation.
- [xii] That the grant of this Environment Clearance is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time being in force, rests with the industry/unit/project proponent. Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section 16 of National Green Tribunal Act, 2010.
- [xiii] The methodology of mining shall be strictly as per orders passed by Hon'ble NGT Hon'ble Supreme Court from time to time.
- [xiv] The Project Proponent shall not disturb/damage the position of studs in river bed and also not to damage the river banks and not to degrade the river bed in any manner.
- [xv] Any area which has been banned by any authority/courts shall not be used for mining activity.
- [xvi] Distance of mining to be maintained from Pucca Hydraulic structure/ Bridges shall be as per approved mining plan/ guideline issued by MoEF & CC/ Court Order.

[xvii] Quantity of mining allowed in the river will be actual replenishment or mining allowed whichever is less.

[xviii] The Project Proponent should set the Probable replenishment checked from the reputed institution.

Sd/-
Member Secretary,
State Level Environment Impact
Assessment Authority, Haryana, Panchkula.

Endst. No. IAA/HR/2016/476-9

Dated: 27.06.2016

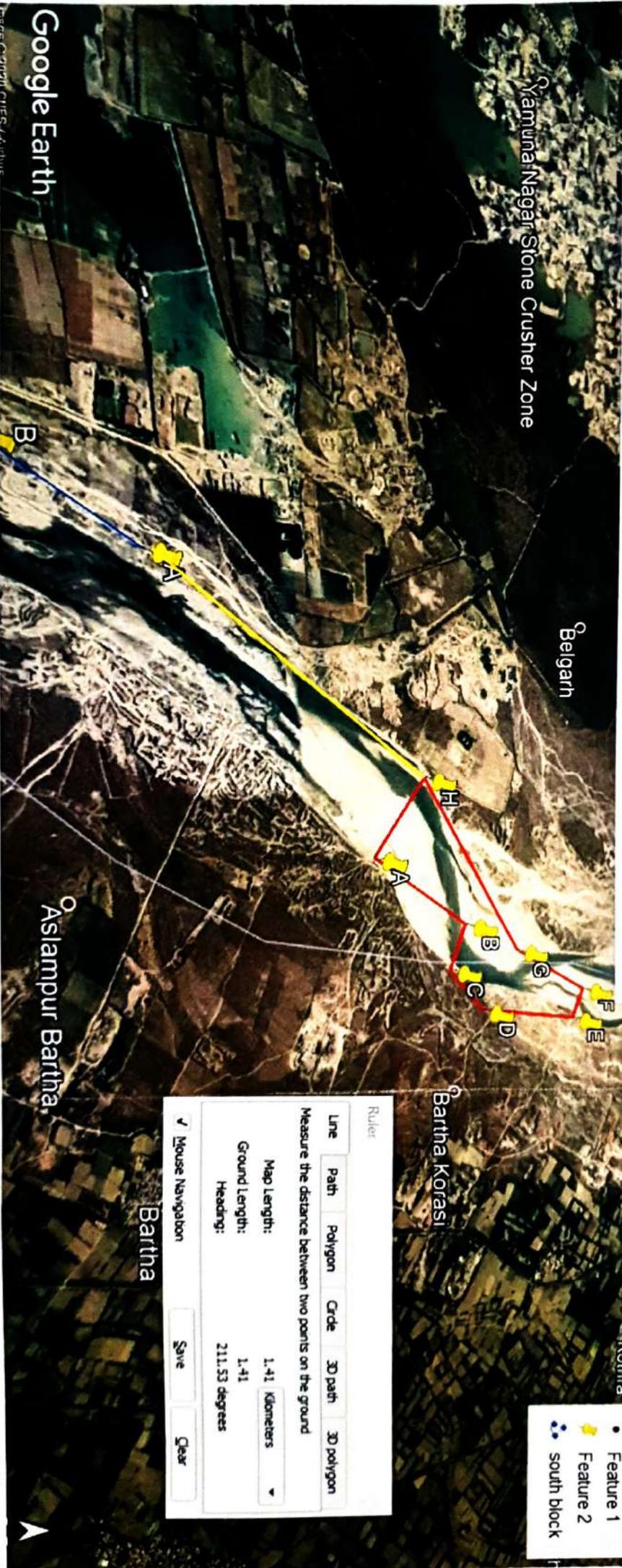
A copy of the above is forwarded to the following:

1. The Director (IA Division), MoEF&CC, GoI, Indra Paryavaran Bhavan, Zorbagh Road-New Delhi.
2. The Regional office, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Government of India, Bay's no. 24-25, Sector 31-A, Dakshin Marg, Chandigarh.
3. The Chairman, Haryana State Pollution Control Board, C-11, Sector-6, Pkl.
4. The Director General, Mines & Geology Department Haryana, Chandigarh.

Sd/-
Member Secretary,
State Level Environment Impact
Assessment Authority, Haryana, Panchkula.

Nearest Distance from Belgarh South(Haryana) to Bartha Korsi (UP)

Write a description for your map.



Legend

- Area
- Feature 1
- Feature 2
- south block

Ruler

Line Path Polygon Circle 3D path 3D polygon

Measure the distance between two points on the ground

Map Length: 1.41 Kilometers

Ground Length: 1.41

Heading: 211.53 degrees

Mouse Navigation

Bartha

Save Clear

प्रपक,

डा० रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 12 जून 2020

विषय: जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में Modification (सुधार) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू के सुव्यवस्थित खनन सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनवरी 2020, में "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" गाईडलाइन्स निर्गत की गई है। उक्त गाईडलाइन्स में Preparation of District Survey Report के प्रस्तर 4.1.1(a) में उल्लिखित है कि "District Survey Report for sand mining shall be prepared before the auction/e-auction/grant of the mining lease/Letter of Intent (LOI) by Mining Department or department dealing the mining activity in respective states."

2. उक्त गाईडलाइन के अनुसार खनन क्षेत्रों की ई-निविदा/ई-नीलामी/ई निविदा सह ई नीलामी/खनन पट्टे की स्वीकृति/आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार किया जाना है। उक्त व्यवस्था अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आंकलन (Environmental Impact Assessment) अधिसूचना/आदेश जारी होने तक जनपदों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रों के प्रस्तावित/संशोधन संयोजन के लम्बित प्रस्तावों तथा नये प्रस्तावों के परीक्षण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन के आदेश सं०-790/86-2020-01(सा०)/2020 दिनांक 01.06.2020(छायाप्रति संलग्न) द्वारा तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

3. उक्त के सन्दर्भ में अपेक्षित है कि अपने-अपने जनपदों में खनन हेतु उपयुक्त राजस्व ग्राम समाज एवं निजी भूमि पर उपलब्ध उपखनिजों के क्षेत्रों का गठन कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्ताव अल्प अवधि हेतु जनपद की वेबसाइट पर अपलोड करके तत्सम्बन्धी विवरण अनुमोदन हेतु शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराये। यदि किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका भी निराकरण कर निराकरण आख्या से शासन एवं निदेशालय को अवगत कराये। इस सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर ले कि जिले में कोई खनन क्षेत्र रिक्त न रह पाये जिससे खनिज की उपलब्धता के साथ ही सम्भावित अवैध खनन का रोका जा सके।

अतः वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपदों में तैयार की गयी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीया,

(डा० रीशान जैकब)

सचिव,

संख्या: (1)/86-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग,
संख्या - /86-2020-01(सा0)/2020
लखनऊ दिनांक 01 जून, 2020
कार्यालय ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बालू के सुव्यवस्थित खनन सम्बन्धी प्रक्रिया के सम्बन्ध में जनवरी 2020, में "Enforcement & Monitoring guidelines for Sand Mining" गाइडलाइन्स निर्गत की गई है। उक्त गाइडलाइन्स के प्रस्तर 4.1.1(a) के अनुसार खनन क्षेत्रों की नीलामी/ई-नीलामी/खनन पट्टे की स्वीकृति/आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) तैयार किया जाना है। अतः उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment) अधिपूचना/आदेश जारी होने तक जनपदों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्षेत्रों के प्रस्तावित संसाधन/संयोजन के लम्बित प्रस्तावों तथा नये प्रस्तावों के परीक्षण हेतु एतद्वारा निम्नवत् तकनीकी समिति गठित की जाती है :-

1	मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	अध्यक्ष
2	संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य
3	अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
4	निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
6	प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
7	श्री माईनुद्दीन, भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य सचिव
8	श्री शशांक शर्मा, सहायक भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0	सदस्य

2. उक्त गाइडलाइन्स के अन्तर्गत जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी आधार पर परीक्षण कर समिति द्वारा सस्तुति सहित शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।

डॉ० रोशन जैकब
सचिव।

संख्या: 790 (1)/86-2020-तद्दिनांक

उक्त प्रेषित विनिलिखित को सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग/प्रमुख सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/प्रमुख सचिव, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अध्यक्ष राजस्व परिषद/निदेशक, पर्यावरण निदेशालय/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 का इस आशय से प्रेषित कि, उक्त समिति में प्रकरण से अभिज्ञ अधिकारी को प्राथमिकता के

आधार पर नामित करते हुये निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि समिति की बैठक यथाशीघ्र आहूत की जा सके।

- 3 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र सं०-1883/एम-228/2017(खनन नीति)(IV) दिनांक 20.02.2020 के सन्दर्भ में।
- 4 समिति के समस्त सदस्यगण (द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० लखनऊ)।
- 5 गार्ड फाईल।

आज्ञा स



(हृदय नारायण सिंह यादव)

अनु सचिव।

प्रेषक,

डॉ० रोशन जैकब,
सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक 17, अप्रैल 2020

विषय :- प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुए खनन संकिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश सं०-40-3/2020DM-I(A) दिनांक-15.04.2020 के माध्यम से जनसामान्य के कठिनाइया को देखते हुए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों (Select Additional Activities), जिसमें खनिजों के उत्पादन/परिवहन सम्मिलित है, को दिनांक-20.04.2020 से अनुमति दिये जाने के निर्देश दिये गये है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में चिन्हित कोविड-19 के हाटस्पॉट को छोड़कर शेष क्षेत्रों में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रारम्भ किया जाये :-

1. नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गार्डलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जाये।
2. खनिजों के खनन/परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारको से खदानों में कोविड मैनेजमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना प्राप्त किया जाये, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों/श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था, प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सैनेटाइजेशन आदि का उल्लेख हो।
3. वर्तमान में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण खनिजों की मांग काफी कम है तथा दिनांक-01 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होने वाले मानसून सत्र के दौरान खनिजों का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश में खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान में खनिजों का भण्डारण किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए नये भण्डारण अनुज्ञप्ति/नवीनीकरण आवेदन पत्रों को नियमानुसार शीघ्रतापूर्वक स्वीकृत किया जाये।

4. शासकीय परियोजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के आधार पर खनिकों की आयुर्विधि की प्राथमिकता प्रदान की जाये।
 5. वर्तमान में दिनांक-22.03.2020 से लाकडाउन के दौरान खनिकों पर लागू सभी परिसरों पर परिवहन का कार्य बन्द है। प्रदेश में खनिक उद्योग एवं परिहारधारकों को पोषण हेतु किये जाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश सम्बन्धित (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 44(ख) एवं नियम-68 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत माह अप्रैल-2020 का दस मासिक किस्त की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जायेगा कि माह अप्रैल-2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिजों की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अंतिम भुगतान प्राप्त की जायेगी।
 6. खान मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश एवं तत्काल में भूतत्व एवं खनिक उद्योग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश एम0-04जी0आई0/86-2020 दिनांक 13.03.2020 के अनुसार कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु जनपद की परिस्थितियों एवं तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं एवं प्राणात्मकता की आवश्यकताओं हेतु डी0एम0एफ0 निधि से जिलाधिकारी द्वारा व्यय किया जा सकता है।
3. अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भारतीय

(डॉ० नरेश चक्रवर्ती)
सचिव।

संख्या (1)/86-2020-तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) निर्देशक भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 62 / एम0-228/2017-खनिक नीति(कोविड)/(iv) दिनांक-15.04.2020 के अन्तर्गत।
- (2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डॉ० नरेश चक्रवर्ती)
सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी सहारपुर
(खनन अनुभाग)

संख्या-18

20

पत्रांक 3404 / ख0अनु0 / खनन लिपिक / 2020

दिनांक 15/5/2020

आदेश

सचिव, उ0प्र0 शासन, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, लखनऊ के आदेश संख्या 05जी0आई0/86-2020-14 (सामान्य) दिनांक 17.04.2020 द्वारा प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुरक्षित करते हुए खनन संक्रिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में जन सामान्य की कठिनाईयों को देखते हुये चयनित अतिरिक्त गतिविधियों जिसमें खनिज के उत्पादन/परिवहन सम्मिलित है, के लिये निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जनपद सहारनपुर में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत खनिजों के खनन/परिवहन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जायेंगी।
- 2- खनिजों के खनन/परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारक/बालू भण्डारण अनुज्ञप्ति धारक से कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना दी जायेगी।
- 3- मशीन और कर्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कर्मिकों/श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था में प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्था की जायेगी।
- 4- कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं दो कर्मिकों/श्रमिकों के मध्य कम से कम एक-एक मीटर की दूरी बनाये रखते हुए नियोजित कर्मिकों/श्रमिकों की सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क/गमछा, सैनेटाईजर एवं हैण्डवास/साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा।
- 5- पेयजल, साफ सफाई/स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी, जिसमें खनन पट्टा क्षेत्र में तैनात कर्मिकों/श्रमिकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।
- 6- कर्मिकों/श्रमिकों हेतु हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाए।
- 7- कर्मिकों एवं श्रमिकों द्वारा होम मेड फेस मास्क/गमछा का प्रयोग करते हुए नाक व मुह को ढक कर रखा जाएगा।
- 8- मदिरा पान, धूमपान एवं तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
- 9- सर्दी, खाँसी, जुकाम से पीडित व्यक्ति को कार्य मुक्त रखा जाए एवं इसकी सूचना तत्काल उपजिलाधिकारी सहित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहारनपुर को देना अनिवार्य होगा।
- 10- खनन संक्रिया में पूर्व से योजित श्रमिक जोकि लॉक डाउन के कारण बाहर नहीं गये हैं और कार्य स्थल पर ही रुके हैं, उन्हीं श्रमिकों से कार्य कराया जाये।
- 11- अपशिष्ट व कूड़ा कचरा आदि के निस्तारण के लिये बंद कूड़ेदान की व्यवस्था खनन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से किया जाए।
- 12- आम जनमानस से आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) मोबाईल में डाउन लोड कर उपयोग किये जाना अनिवार्य होगा।
- 13- कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 14- खनन संक्रिया में लगे श्रमिक/मजदूर जनपद के चिन्हित Hot Spot Area से नहीं आएंगे।
- 15- जो भी श्रमिक/मजदूर खनन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके रहने और खाने की व्यवस्था सम्बन्धित पट्टेधारक द्वारा की जाएगी।

उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त शर्तों के पालन पाये जाने पर खनन संक्रियाओं को रोके जाने के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक/संचालक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

जिलाधिकारी
सहारनपुर

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन लखनऊ।
- 2-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन लखनऊ।
- 3- आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
- 4- पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर, मडणल सहारनपुर।
- 5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर
- 6- समस्त उपजिलाधिकारी/समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारी सहारनपुर
- 7- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहारनपुर
- 8- जिला सूचना अधिकारी, सहारनपुर को निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
- 9- श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सहारनपुर
- 10- सम्बन्धित खननपट्टाधारक/भण्डारण/अनुज्ञप्तिधारक/खनन अनुज्ञा पत्र धारक को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी
सहारनपुर